घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 263- शुक्रवार 24- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

संसद परिसर में पेपर लीक पर सियासी टकराव...प्रदर्शन के दौरान आमने-सामने आए एनडीए और विपक्षी सांसद

प्रियंका नारे लगाते एनडीए सांसदों के पास पहुंचीं...सुरक्षाकर्मियों ने रोका...

नई दिल्ली,23 जुलाई 2026। संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को संसद भवन के बाहर एनडीए और विपक्ष आमने-सामने आ गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष के सामने एनडीए के सांसद भी विरोध प्रदर्शन में उतर गए। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनडीए सांसद पीएम आवास के बाहर 21 जुलाई को राहुल के धरने का विरोध कर रहे हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी एनडीए सांसदों के बिल्कुल करीब चली गईं। सुरक्षाकर्मियों ने बीच में आकर उन्हें रोका। संसद के भीतर भी हंगामा जारी रहा। इसके कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 2 बजे लोकसभा में कार्यवाही शुरू हुई तो भारी हंगामा शुरू हो गया। इस पर सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे के चलते 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब दोबारा सदन शुरू हुआ तो सांसदों ने फिर से हंगामा कर दिया। इसके बाद राज्यसभा भी 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सिब्बल बोले...सरकार पहले अपने नेताओं पर फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए : राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार पहले अपनी पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए,जिन पर पहले गंभीर आरोप लगाए गए थे और बाद में उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया गया। उन्होंने सवाल किया कि उनके खिलाफ सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही और पहले से चल रही जांच क्यों रोक दी गई। सिब्बल ने कहा कि छात्रों का आंदोलन 28 जून से चल रहा है और 25 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान सरकार ने न तो छात्रों से बातचीत की और न ही उनकी चिंताओं पर कोई बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब छात्र भूख हड़ताल पर बैठे थे, तब सरकार चुप रही और अब युवाओं के बढ़ते गुस्से को देखकर सरकार सक्रिय हुई है।

राज्यसभा में खड़गे के आरोपों पर नड्डा बोले...विपक्ष का व्यवहार गैर-जिम्मेदाराना

राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों पर जवाब दिया। नड्डा ने कहा- विपक्ष का व्यवहार बेहद गैर-जिम्मेदाराना है। वे न तो चर्चा करना चाहते हैं और न ही सदन चलने देना चाहते हैं।

प्रियंका बोलीं...पीएम मंगल मिशन का श्रेय लेते हैं तो युवाओं के भविष्य की जिम्मेदारी भी लें...

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा- प्रधानमंत्री देश की हर उपलब्धि और मंगल मिशन तक का श्रेय लेते हैं, जो हमारे युवाओं और देशवासियों की मेहनत का नतीजा है। अब उनके जिम्मेदारी लेने का समय है।

रिजिजू बोले...नीट पेपर लीक पर सरकार किसी भी तरीके से चर्चा को तैयार

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में कहा...सरकार लोकसभा और राज्यसभा में नीट पेपर लीक पर विपक्ष जिस तरीके से, जिस तारीख को और जितनी देर चाहे, चर्चा के लिए तैयार है।

रिजिजू बोले...विपक्ष से साथ जोड़कर अपील,चर्चा कब करनी है तय करें

हमने कल भी अपील की थी और आज भी सदन से अपील कर रहे हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर भी बात की है। उन्हें सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया है हम हाथ जोड़कर विपक्ष से अनुरोध करते हैं कि वह तय करे कि चर्चा कब शुरू करनी है। सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष शर्तें रख रहा है। बहाने मत बनाइए,क्योंकि जब आप शर्तें और बहाने रखते हैं तो सभी समझ जाते हैं कि आप चर्चा से बचना चाहते हैं। आज एनडीए के सांसदों ने भी प्रदर्शन किया और देशभर में नीट पेपर लीक पर तुरंत चर्चा की मांग की। किसी भी परीक्षा में जिस-जिस राज्य में पेपर लीक हुआ है, उन सभी पर चर्चा होना जरूरी है। इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।

किरेन रिजिजू बोले...नीट पर चर्चा चाहते थे,लेकिन विपक्ष ने शर्तें रख दीं

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स पोस्ट का हवाला देते हुए कहा कि सरकार नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा शुरू करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि बुधवार को कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेताओं से बातचीत हुई थी और सभी ने समाधान निकालने की बात कही थी, लेकिन बाद में विपक्ष ने शर्तें रखनी शुरू कर दीं। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने संसद परिसर में कहा कि कांग्रेस बैनर लेकर प्रदर्शन कर सदन का समय बर्बाद कर रही है और जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, उनसे भाग रही है। राज्यसभा में भी सुबह 11 बजे हंगामे के साथ कार्यवाही की शुरुआत हुई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज जो बयान दिया है वह भड़काऊ है।

पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे

युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं,दोषी बख्शे नहीं जाएंगे : पीएम मोदी

नई दिल्ली,23 जुलाई 2026। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऐलान किया कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम का यह ऐलान कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष के प्रदर्शन के बीच आया है। सीजेपी पिछले 34 दिन से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वहीं, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 26 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। वे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं उनका इलाज चल रहा है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पेपर लीक केस के लिए पहली बार फास्ट ट्रैक कोर्ट

देश में अब तक पेपर लीक मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती थी,इसलिए फैसला आने में कई साल लग जाते थे। अब प्रधानमंत्री ने इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है, ताकि फैसला तेजी से हो सके। भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। इनका गठन 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। आयोग ने देशभर में 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए स्पेशल फंड की अनुशंसा की थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड भी बेहतर रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार,रेप और पॉक्सो मामलों के लिए बनी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2019 से 2025 तक 3.06 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा किया है। इन अदालतों में मामलों के निपटारे का रेट 96.28% है, यानी जितने नए मामले आए,लगभग उतने ही मामलों का निपटारा भी हुआ। हालांकि, नए मामले लगातार दर्ज होने के कारण 2025 के अंत तक 2.45 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग थे,जबकि 2024 के अंत में यह संख्या 2.04 लाख थी।

पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को लेकर विपक्षी दलों ने जताया विरोध

पेपर लीक में शामिल लोगों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक्स पोस्ट पर विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद सागरिका घोष ने संसद परिसर से बाहर मीडिया से कहा कि पहले इस्तीफ़ा, फिर चर्चा। हम सदन में नीट पर चर्चा की मांग कर रहे हैं,लेकिन चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। अगर वह इस्तीफा नहीं देते हैं, तो हम चर्चा नहीं करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा क्यों नहीं देंगे? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वहीं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई-एम) के सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि यह विरोध सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहेगा। हम सड़कों पर उतरेंगे। हमने तय किया है कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। हम जरा भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें इस्तीफ़ा देना ही होगा। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि उनके (धर्मेंद्र प्रधान) के कार्यकाल में कितने पेपर लीक हुए, इस पर एक श्वेत पत्र आना चाहिए। कितने लोगों पर मुकदमा चला, कितनों को सजा मिली, कितने जेल गए, कितनों को सजा सुनाई गई, अब तक कुछ नहीं हुआ है।

महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल,एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा जंतर-मंतर ड्यूटी से हटाए गए

नई दिल्ली,23 जुलाई 2026। दिल्ली में सीजेपी के 'चलो संसद' प्रदर्शन के दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने के आरोपों के बाद एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा को जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल की ड्यूटी से हटा दिया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। 20 जुलाई को कथित परीक्षा अनियमितताओं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी के हजारों समर्थक जंतर-मंतर पर जुटे थे। इसी दौरान वायरल वीडियो में एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दिए। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में पुलिस की कथित बर्बरता के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान इस घटना का भी उल्लेख किया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत को बताया कि वीडियो में अधिकारी बिना किसी उकसावे के महिला को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन का उपयोग करने के बजाय सीधे आंसू गैस के गोले छोड़े, जबकि ऐसा अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए था। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

छात्रों के प्रदर्शन पर अन्ना हजारे ने केंद्र से संवाद की अपील की

अहिल्यानगर,23 जुलाई 2026। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर केंद्र सरकार से संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाने के बजाय उससे बातचीत की जानी चाहिए और जवाबदेही तय करना ही सुशासन की पहचान है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में गुरुवार को अन्ना हजारे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों के समर्थन में सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक दो घंटे का मौन आंदोलन किया। इसके बाद वे अपने गांव रालेगण सिद्धि के लिए रवाना हो गए। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे पत्र में हजारे ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और कथित पुलिस कार्रवाई को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में टकराव नहीं, बल्कि संवाद सबसे प्रभावी समाधान है। हजारे ने अपने पत्र में लिखा कि यदि किसी मंत्री की जवाबदेही तय कर इस्तीफा लिया जाता है, तो इससे सरकार कमजोर नहीं होती बल्कि यह पूरे मंत्रिमंडल को जिम्मेदारी का स्पष्ट संदेश देता है और शासन व्यवस्था अधिक जवाबदेह बनती है। अन्ना हजारे ने कहा कि देश के लाखों युवा पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में देरी और बढ़ती बेरोजगारी जैसी समस्याओं से परेशान हैं। इन मुद्दों को केवल कानून-व्यवस्था का विषय मानने के बजाय जनता की वास्तविक चिंता के रूप में देखा जाना चाहिए। बतौर अन्ना हजारे किसी भी गड़बड़ी या घोटाले के सामने आने पर अक्सर जिम्मेदारी निचले स्तर के अधिकारियों पर डाल दी जाती है।

कॉकरोच जनता पार्टी ने भरी हुंकार...आज देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान,सभी जिलों में आंदोलन करने की छात्रों से अपील

नई दिल्ली,23 जुलाई 2026। जंतर-मंतर पर जारी छात्रों के धरना-प्रदर्शन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (कॉकरोच जनता पार्टी) ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने बड़े देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसके साथ ही पार्टी ने आह्वान किया है कि बड़ी संख्या में छात्र इसमें शामिल होकर इसे सफल बनाएं। कॉकरोच जनता पार्टी ने देशभर में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। पार्टी ने छात्रों और युवाओं से बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। यह प्रदर्शन पेपर लीक मामले और छात्रों के तमाम मुद्दों और मांगों को लेकर किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी छात्र लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। सीजेपी ने इस प्रदर्शन की जानकारी एक डिजिटल पंफलेट के जरिये शेयर की है। यह पंफलेट सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट किया जा रहा है। सीजेपी ने लोगों से अपील की है कि वह बड़ी संख्या में पीसफुल प्रोटेस्ट करें और एकजुटता दिखाएं। संगठन ने हर जिले में एक दिन के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील करते हुए कहा है कि यह आंदोलन देशभर में पुलिस कार्रवाई के पीड़ितों के साथ एकजुटता जताने के लिए किया जाएगा। प्रदर्शन आज आयोजित होगा और इसके लिए छात्र संगठनों व अन्य सामाजिक संगठनों से मिलकर लोकल लेवल पर परमिशन और जरूरी व्यवस्थाएं करने को कहा गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन के दौरान इकट्ठा हुए लोगों के सामने छात्रों की मांगों को सार्वजनिक रूप से पढ़ने और पुलिस कार्रवाई का सामना करने वालों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने की अपील की है। संगठन ने बताया है कि प्रदर्शन से संबंधित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, प्रचार सामग्री और ज्ञापन का प्रारूप उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। पोस्टर के अंत में 'इंकलाब जिंदाबाद' और 'भारत माता की जय' के नारों के साथ देशभर के लोगों से इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की गई है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर आंदोलन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बीच बातचीत को लेकर गतिरोध बना हुआ है। एक तरफ जहां सरकार गतिरोध समाप्त करने के लिए बातचीत की मेज पर आने की अपील कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सीजेपी ने अपनी शर्त रख दी है। इसके साथ ही सीजेपी ने शुक्रवार को देशव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका ने साफ किया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के आवास या मंत्रालय में कोई बैठक नहीं होगी। आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार के प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि नड्डा के घर पर कोई बैठक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत करनी है तो यह जंतर-मंतर या किसी बीच की जगह पर हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद होने का मामला कोर्ट पहुंचा,सीजेआई बोले...

जरूरत पड़ी तो करूंगा हस्तक्षेप

नई दिल्ली,23 जुलाई 2026। छात्रों के प्रदर्शन के कारण बंद किए गए सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का मुद्दा गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में उठा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष विकास सिंह ने मांग की कि जिन वकीलों, पक्षकारों और अदालत के कर्मचारियों के पास सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश का वैध पास है, उन्हें सुरक्षा जांच के बाद स्टेशन से आने-जाने की अनुमति दी जाए। विकास सिंह ने कहा कि मेट्रो स्टेशन पर एक ही निकास द्वार है, जहां सभी की अच्छी तरह जांच की जा सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि केवल वैध पास और प्रॉक्सिमिटी कार्ड रखने वालों को बाहर निकलने दिया जाए, जबकि बाकी यात्रियों को दूसरी ट्रेन से आगे भेजा जा सकता है। इस पर मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को इस मामले पर मेट्रो अधिकारियों से बात करने के लिए कहा जा चुका है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला, तो वह स्वयं हस्तक्षेप करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि वकीलों की अनुपस्थिति के कारण किसी भी मामले में उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने सुरक्षा कारणों और 'चलो संसद' प्रदर्शन को देखते हुए सुबह 7:30 बजे से सुप्रीम कोर्ट समेत 16 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं।

गुरुग्राम-मेदांता में 600 जवानों की सिक्योरिटी में सोनम वांगचुक : बोले-भरोसा मिले तो आज ही अनशन खत्म,नड्डा ने कहा-आपकी चिट्ठी मिली,चर्चा कर रहे

गुरुग्राम,23 जुलाई 2026। सोनम वांगचुक के अनशन का गुरुवार को 26वां दिन था। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हुए उन्हें दो दिन हो चुके हैं। बुधवार को उनसे मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और समाजवादी पार्टी के 15 विपक्षी सांसदों को पुलिस ने रोक दिया था। पुलिस और सांसदों के बीच बहस हुई। नाराज सांसद गेट पर ही धरने पर बैठ गए। इसे लेकर करीब एक घंटे तक हंगामा चला। इसके बाद सोनम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज जारी किया, जिसमें कहा- अनशन को 25 दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक जिंदा हूं। कुछ सांसद मुझसे मिलने आए, उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की। मुझे अगर सरकार की तरफ से भरोसा मिले तो मैं आज ही अनशन खत्म करने को तैयार हूं। बस सरकार छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न करे।' उधर, शाम को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वांगचुक ने हमें ओपन लेटर लिखा है। हम जल्दी उस लेटर का जवाब देंगे।

देशभर में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन : बिहार के कटिहार में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज,ईंट-पत्थर चले,हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस से भिड़े कांग्रेसी

नई दिल्ली,23 जुलाई 2026। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में गुरुवार को भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिहार के कटिहार में ष्ठरू ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। छात्र अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो ईंट-पत्थर चलाए गए। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस की कांग्रेसियों से झड़प हो गई। दरभंगा, बेगूसराय,जहानाबाद और कटिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से जमकर ईंट-पत्थर चलाए गए। जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद छात्र उग्र होकर रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। रेलवे ट्रैक से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। इस दौरान पुलिस ने 30 राउंड हवाई फायरिंग की। बेगूसराय में प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। छात्र गेट पर चढ़ गए थे। पुलिस सभी छात्रों से पीछे हटने की अपील की। लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं थे। छात्रों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज किया, ताकि प्रदर्शनकारियों को हटाया जा सके। इस दौरान छात्रों ने जिला प्रशासन की गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी। वहीं, कटिहार में डीएम ऑफिस के बाहर तैनात मजिस्ट्रेट की पत्थरबाजी में आंख फूट गई। वहीं, पटना कॉलेज के पास छात्र फिर सड़कों पर उतरे। अशोक राजपथ पर जाम लगा दिया। छात्रों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। थोड़ी देर बाद पुलिस ने छात्रों को डिटेन किया। उन्हें बस में भरकर ले जाया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। पुलिस लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। केंद्र सरकार तानाशाही हो गई है, हम लोगों के अधिकारों का दमन कर रही है। हम मोदी सरकार से डरने वाले नहीं हैं। खराब शिक्षा नीति के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, क्या मतलब है इसका।

सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से झटका...जमानत रद्द,तीन हफ्तों में सरेंडर आदेश

नई दिल्ली,23 जुलाई 2026। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने मेघालय सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए आरोपी सोनम की जमानत को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने उसे आगामी तीन सप्ताह के भीतर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण (सरेंडर) करने का सख्त आदेश दिया है। यह पूरा मामला ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हुई रहस्यमयी हत्या से जुड़ा हुआ है, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी।

छह महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने के निर्देश : सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इस सनसनीखेज मामले का निचली अदालत में ट्रायल आगामी छह महीने की समयावधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित छह महीने के इस समय अंतराल में ट्रायल पूरा नहीं हो पाता है, तो आरोपी सोनम रघुवंशी के पास यह कानूनी विकल्प होगा कि वह निचली अदालत या उच्च न्यायालय में दोबारा अपनी जमानत याचिका दाखिल कर सकती है। हालांकि, फिलहाल उसे अदालत के आदेशानुसार तीन सप्ताह के भीतर हर हाल में सरेंडर करना होगा।

कोर्ट द्वारा सोनम के वकीलों को दिए गए दो विकल्प : बीते मंगलवार को चली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सोनम रघुवंशी के वकीलों के समक्ष दो स्पष्ट विकल्प रखे थे। अदालत ने पूछा था कि क्या सोनम खुद अपनी इच्छा से इस मामले में सरेंडर करेगी, या फिर न्यायालय उसकी जमानत को खारिज करने के संबंध में अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। वहीं दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने लिखित जवाब में आरोपी सोनम ने खुद को पूरी तरह बेकसूर बताया था। उसने दावा किया था कि उसे इस गंभीर मामले में झूठा फंसाया गया है और उसके खिलाफ अभियोजन पक्ष का पूरा मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर ही आधारित है। मेघालय सरकार की पैरवी करते हुए सॉलिसिटर जनरल (स्त) तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जोरदार दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों की टाइपिंग के दौरान केवल एक कानूनी धारा के नंबर को लिखने में मामूली तकनीकी गलती हो गई थी।

संपादकीय

जनमानस को समझने में विफल विपक्ष

पिछले एक महीने में राष्ट्रीय राजनीति तथा संसद का समीकरण जिस तरह से बदला है उसकी कल्पना किसी को नहीं थी। क्या भाजपा या राजग विरोधी दलों, नेताओं में से किसी ने सोचा था कि बंगाल का चुनाव परिणाम आते ही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टूट जाएगी और उसके 28 में से 20 लोकसभा सदस्य अलग समूह बनाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के समर्थन की घोषणा करेंगे? इस सिलसिले की शुरुआत आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सदस्यों के भाजपा में शामिल होने से हुई। टीएमसी के राज्यसभा सदस्यों के भी इस्तीफे हो रहे हैं। एक तरह से ममता बनर्जी का खुद की तृणमूल पर कोई अधिकार नहीं रह गया है। उद्धव ठाकरे की बची-खुची शिवसेना भी उनके हाथ से फिसलती जा रही है।

बीते दिनों उनके छह सांसद राजग के साथ चले गए। पहले भी कुछ सांसद एवं विधायक एक दल छोड़कर दूसरी ओर गए हैं, लेकिन इस तरह की घटना राष्ट्रीय राजनीति में पहले कभी नहीं हुई। माहौल ऐसा बन गया है कि अनेक पार्टियों के शीर्ष नेता दिन-रात इस भय में हैं कि पता नहीं उनके कितने सांसद या विधायक अचानक साथ छोड़कर दूसरी ओर जाने की घोषणा कर दें।

पहली दृष्टि में ऐसा लगता है कि भाजपा अंदर ही अंदर नेताओं को दल-बदल के लिए तैयार करा रही है, पर क्या यही सच है?

कांग्रेस या अन्य पार्टियां भाजपा पर भले आरोप लगाएं, किंतु इस प्रक्रिया से उन सबको भयभीत होना चाहिए, जो बदलते हुए सामूहिक राष्ट्रीय मानस और धारा के विपरीत काम कर रहे हैं।

विपक्ष के इस आरोप को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा ने ईडी, सीबीआइ, इनकम टैक्स और अन्य दबावों से यह स्थिति पैदा की है। इतनी बड़ी संख्या में सांसद और विधायक वर्षों का साथ छोड़कर सीधे भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ जा रहे हैं तो यह परिघटना सामान्य नहीं मानी जाएगी। इनमें से कितने सांसद, विधायक होंगे जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले हैं?

सारे सांसदों, विधायकों में से बहुत कम पर भ्रष्टाचार या अपराध के संगीन मामले हैं। बदलते घटनाक्रम में शरद पवार और सुप्रिया सुले के कदमों ने जता दिया है कि इन सबमें बुद्धिमान वही निकले। अगर शरद पवार ने राजग के साथ जाने का संकेत नहीं दिया होता तो उनके आठ में से छह सांसद और सभी दसों विधायक साथ छोड़कर चले जाते।

हालांकि शरद पवार ने राष्ट्रीय स्तर पर बदलती राजनीति, जनमानस और धारा को समझने में काफी देर की। अगर वह पहले समझ गए होते और महाविकास आघाड़ी या आइएनडीआइए के सपने में नहीं जीते तो उनकी पार्टी एक होती और शीर्ष नेता वही माने जाते।सांसदों-विधायकों के टूटने की घटना को गत 17 अप्रैल को 131वें संविधान संशोधन विधेयक के लोकसभा में गिर जाने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यानी विपक्षी दलों के सांसदों के अंदर भय पैदा हो गया है कि महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण का हमने समर्थन नहीं किया और विरोध में चले गए तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे, किंतु इसी कारण केवल सांसद और विधायक भाजपा या राज्य की ओर आ रहे हों, यह मान लेना भी पूरी स्थिति का सामान्य विश्लेषण होगा।

स्मार्ट मीटर : हंगामा क्यों है बरपा

विकास शर्मा
रायपुर,छत्तीसगढ़

इन दिनों छत्तीसगढ़ में बिजली बिल को लेकर चर्चा जोरों पर है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर तो कुछ राजनीतिक रूप से स्मार्ट मीटर को बढ़े हुए बिजली बिल का दोषी ठहरा रहे हैं। चर्चा के केन्द्र में आए स्मार्ट मीटर को लेकर जिज्ञासा भी बढ़ी है। एक उपभोक्ता के नजरिए से स्मार्ट मीटर को देखना भी चाहिए। असल में स्मार्ट मीटर स्थापना का निर्णय देश की ऊर्जा जरूरतों, गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति तथा सबके लिए ऊर्जा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए व्यापक कार्ययोजना का हिस्सा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में सुधारवादी कदम के रूप में यह अपनी कितनी उपयोगिता साबित कर पाया है यह जानना जरूरी।

क्या है सुधारवादी कदम

देश में विद्युत ऊर्जा की मांग बीते एक डेढ़ दशक में तेजी से बढ़ी है। वर्ष 2013-14 में जहाँ 136 गीगावॉट की अधिकतम मांग थी वह इस वर्ष 270 गीगावॉट को पार कर गई। ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि ,पारेषण तंत्र की मजबूती और वितरण प्रणाली का सुदृणीकरण आवश्यक हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण था तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि (एटीएंडसी लॉस) को न्यूनतम स्तर पर लाना। हानि को कम करने तथा पारदर्शी वितरण एवं बिलिंग व्यवस्था की मजबूती के लिए 2021 में देशभर में पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना ((आरडीएसएस) की शुरूआत की गई। योजना के तहत पुराने विदयुत कंडक्टर को बदलना, उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि, फीडर पृथक्करण (सेपरेशन) , एनर्जी ऑडिट, ट्रांसफार्मर स्तर से लेकर उपभोक्ताओं तक उन्नत प्रौद्योगिकी वाले स्मार्ट मीटर की स्थापना शामिल है।

कितना हुआ बदलाव

आरडीएसएस योजना के विभिन्न उपायों जिसमें स्मार्ट मीटर की स्थापना भी शामिल है के लागू होने के बाद परिणाम चौंकाने वाले हैं। विद्युत मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्ष 2020-21 में विद्युत हानि 21.91 प्रतिशत थी जो 2024-25 में गिरकर 15.04 प्रतिशत पहुंच गई है। देश में 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। बिहार,असम ,आंध्रप्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में सबसे अधिक सकारात्मक बदलाव देखे गए हैं। बिहार में विद्युत हानि 39.39 प्रतिशत से 15.51 प्रतिशत ,असम में 23.39 प्रतिशत से 15.44 प्रतिशत , आँध्रप्रदेश में 20.4 प्रतिशत से घटकर 7.9 प्रतिशत तक आ चुकी है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ और अहम हो जाता है क्योंकि सरकार हर वर्ग के उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष तौर पर रियायती बिजली उपलब्ध कराती है। योजना के क्रियान्वयन से यहाँ यह घाटा बीते दो वर्ष में ही 03 प्रतिशत घटकर 13 प्रतिशत से नीचे आ गया है। जबकि राज्य निर्माण के समय 34 प्रतिशत हानि का भार झेल रहे थे। यह विद्युत वितरण क्षेत्र में व्यापक सुधार के परिणाम को दर्शाता है।

बिजली की बढ़ती खपत

देश में बिजली की खपत बढ़ने में औद्योगिक, परिवहन , कृषि , व्यवसायिक से लेकर घरेलू उपभोक्ताओं की भूमिका अहम है। छत्तीसगढ़ में ही घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत खपत में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। प्रति व्यक्ति

बिजली खपत के मामले में छत्तीसगढ़ देश में पांचवे स्थान पर है। बीते एक वर्ष में ही प्रदेश में अधिकतम मांग 300 मेगावॉट बढ़कर 7300 मेगावॉट को पार कर गई है। राज्य में प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि , वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और गर्मी के लंबे कालखण्ड ने बिजली की खपत को और बढ़ा दिया है। परिवहन विभाग के आँकड़ों के मुताबिक प्रदेश में ई व्हीकल जिसमें दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया वाहन शामिल हैं की पंजीकृत संख्या 203934 है। इसमें अकेले ई रिक्शा ही 30 हजार से अधिक हैं तथा 1 लाख 30 हजार से अधिक दो पहिया वाहन जो बिजली से ही चार्ज होते हैं। इसके अलावा घरेलू ईंधन के तौर पर इलेक्ट्रिक स्टोव एवं इंडक्शन का उपयोग एक वर्ष के अंदर ही तेजी से बढ़ा है। वातानुकूलन के लिए एसी का उपयोग अब विलासिता की बात नहीं रही। आईईए के रिपोर्ट के मुताबित देश में 10-12 प्रतिशत की दर से एसी का उपयोग बढ़ता जा रहा है। यह आँकड़ा देश के स्तर पर ही नहीं प्रदेश के लिए भी बढ़ती जरूरतों को इंगित करता है।

स्मार्ट मीटर का विरोध कितना सही

बढ़े विद्युत बिल को आधार बनाकर स्मार्ट मीटर का विरोध किया जा रहा है। यह विरोध राजनीतिक भी होता जा रहा है। जनता की भावनाओं का राजनीतिक उपयोग होता रहा है संभव है इस मसले में भी हो पर इस विरोध में बड़ा विरोधाभास भी दिखता है। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर की स्थापना का निर्णय से लेकर निविदा तक एक दल की सरकार रही वहीं दूसरे दल की सरकार ने आकर उसे आगे बढ़ाया। इसी प्रकार देश के कई राज्यों में विरोध कर रहे दलों की सरकार है जो अपने यहाँ स्मार्ट मीटर को बढ़ावा दे रहे हैं या प्रारंभ करने में शामिल थे। इसमें हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं। इसलिए ऐसे में यह संदेह के दायरे में है कि विरोध स्मार्ट मीटर का है या राजनीतिक। कुछ सोशल मीडिया में अपूर्ण तथ्यों के आधार पर स्मार्ट मीटर का विरोध भी जोरों से हो रहा है। इससे वे परोक्ष रूप से बिजली क्षेत्र के सुधारक कदमों को रोकने का ही प्रयास कर रहे हैं।

क्या है उपाए

एक उपभोक्ता का अधिक बिल आना निश्चित ही उसके बजट को सीधे प्रभावित करता है। ऐसे में यदि उपभोक्ता को बिल पर संदेह है तो निराकरण के कई मंच हैं। अच्छी बात तो स्मार्ट मीटर के मामले में यही है कि वो उपभोक्ता को अधिक सशक्त बनाता है। खपत पर निगरानी से लेकर नियंत्रण की सुविधा मोबाइल पर उपलब्ध है। संदेह का समाधान मीटर की जाँच कर भी कर सकते हैं। केन्द्र सरकार के निर्देशों के तहत प्रदेश में मीटर की जाँच की सुविधा उपलब्ध है। शिकायत हो तो चेक मीटर से जाँच , असंतुष्ट होने पर एनएबीएल प्रमाणित प्रदेश की मीटर जाँच प्रयोगशाला में भी जाँच की सकती है। भिलाई स्थित केन्द्रीय जाँच प्रयोगशाला के आँकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं कि बीते वर्ष में 355 स्मार्ट मीटरों की जांच में किसी में रीडिंग संबंधी त्रुटि नहीं पाई गई।

उपभोक्ता जागरूकता है जरूरी

बढ़े बिल को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता पर कुछ बातों पर ध्यान देकर उपभोक्ता अपने बिल पर नियंत्रण कर सकता है। एसी के उपयोग में तापमान से बड़ा खेल होता है। 24 डिग्री से कम तापमान यानि प्रत्येक डिग्री में कमी 6 प्रतिशत तक अधिक बिल का कारण। उपभोक्ता सजग रहें कि विदयुत कनेक्शन लेते वक्त उन्होंने कितने लोड की अनुमति ली थी क्योंकि स्मार्ट मीटर इसपर निगाह बनाए हुए हैं कि लगातार तीन माह तक स्वीकृत भार के बढ़ने पर अपने आप उपभोक्ता को बढ़े स्वीकृत भार की श्रेणी में लाता है और अतिरिक्त भार के लिए शुल्क जोड़कर बिल में भेज रहा है। प्रदेश में यह बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के साथ हुआ है जिससे वे स्मार्ट मीटर में अधिक बिलिंग के तौर पर देख रहे हैं।

उपभोक्ता और राष्ट्रहित

विद्युत क्षेत्र के सुधारवादी कदमों का देश के सभी राज्यों में लाभ दिख रहा है। बिजली की निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति बिना बेहतर प्रौद्योगिकी के संभव नहीं है। आज यदि हर क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ लिया जा रहा है। ऐसे में देशहित और उपभोक्ता हित को केन्द्र में रखकर किए जा रहे बदलावों को यदि भ्रामकता का शिकार बनाया जाएगा तो भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र का सशक्तिकरण प्रभावित होगा। एक सजग और जिम्मेदार विद्युत उपभोक्ता अपने हितों को राष्ट्रहित के साथ जोड़कर देखेगा तभी आने वाली पीढ़ी को ऊर्जा सशक्त राष्ट्र सौंपने में सफल होगा।

कर-संस्कृति : विकसित भारत का अदृश्य संविधान

कृति आर.के.जैन,बड़वानी,मध्यप्रदेश

राष्ट्र की शक्ति केवल मतगणना से नहीं,करगणना से भी मापी जाती है। मतपत्र नागरिक की राजनीतिक चेतना का प्रतीक है, तो आयकर रिटर्न उसकी आर्थिक निष्ठा का। विडंबना यह है कि मतदान पर व्यापक विमर्श होता है, पर कर-अनुशासन पर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखती। जबकि किसी भी आधुनिक राष्ट्र की स्थिरता का वास्तविक आधार उसकी कर-संस्कृति होती है। 24 जुलाई का आयकर दिवस इसी मौन सत्य का स्मरण कराता है कि राष्ट्र का भविष्य केवल बजट नहीं, बल्कि करोड़ों ईमानदार करदाताओं के निष्ठापूर्ण योगदान से आकार लेता है। विकसित भारत का आधार केवल नीतियाँ नहीं, बल्कि उत्तरदायी कर-संस्कृति है। इसलिए आयकर दिवस किसी विभागीय औपचारिकता का नहीं, आर्थिक नागरिकता के सम्मान का अवसर है। इतिहास गवाह है कि समृद्ध राष्ट्रों की नींव केवल संसाधनों पर नहीं, सुदृढ़ कर-संस्कृति पर टिकी होती है। भारत में आधुनिक आयकर व्यवस्था का औपचारिक आरंभ 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत आयकर अधिनियम से हुआ, किंतु स्वतंत्र भारत ने इसे केवल राजस्व-संग्रह नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय विकास का माध्यम बनाया। 1961 के आयकर अधिनियम के बाद सरलीकरण की दिशा में नया आयकर कानून भी प्रस्तावित/लागू होने की प्रक्रिया में है, प्रत्यक्ष कर प्रशासन में सुधार, कंप्यूटरीकरण, केंद्रीकृत प्रसंस्करण और डिजिटल कर प्रणाली उसी दृष्टि के क्रमिक विस्तार हैं। आज भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है और वैश्विक संस्थाएँ उसे आने वाले दशक का विकास-प्रेरक मान रही हैं। इस उपलब्धि के मूल में करोड़ों ईमानदार करदाताओं से निर्मित वही राजस्व है, जिसने विकास की गति को निरंतर बनाए रखा।

हर सार्वजनिक उपलब्धि के पीछे एक मौन निवेश छिपा होता है—करदाता का। राष्ट्रीय राजमार्गों, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं,नई शिक्षा नीति के अनुरूप विकसित संस्थानों, रक्षा आधुनिकीकरण,डिजिटल अवसंरचना,अंतरिक्ष अनुसंधान, जल संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की वास्तविक नींव ईमानदारी से अदा किए गए कर पर टिकी है। नागरिक अपनी आय का एक अंश राष्ट्र को देकर केवल राजस्व नहीं देता, बल्कि समान अवसरों वाले भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है। इसलिए विकसित देशों में कर भुगतान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। भारत भी अब उसी दिशा में बढ़ रहा है, जहाँ करदाता राजस्व का स्रोत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रगति का सह-शिल्पी माना जाता है।

कर प्रशासन का नया चेहरा कानूनों से कम, तकनीक से अधिक गढ़ा गया है। कभी आयकर कार्यालयों के चक्कर, कागजी फाइलें और लंबी प्रतीक्षाएँ करदाताओं की विवशता थीं; आज फेसलेस असेसमेंट,प्री-फिल्ड आयकर रिटर्न,ऑनलाइन सत्यापन, डिजिटल भुगतान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जोखिम विश्लेषण ने प्रक्रिया को पारदर्शी, त्वरित और विश्वसनीय बना दिया है। प्रत्यक्ष कर संग्रह में निरंतर वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि सरल व्यवस्था स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देती है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों ने भी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में भारत की प्रगति को उल्लेखनीय माना है। तकनीक का उद्देश्य केवल निगरानी नहीं, बल्कि करदाता और शासन के बीच भरोसे का स्थायी सेतु बनाना है। इसलिए आज करदाता व्यवस्था से डरता नहीं, उस पर भरोसा करता है।

कर भुगतान का सबसे बड़ा लाभ सरकार नहीं, स्वयं करदाता प्राप्त करता है। नियमित आयकर रिटर्न आय, व्यय, निवेश और बचत का अनुशासित लेखा विकसित करता है, जो बैंकिंग, ऋण, उद्यमिता और वित्तीय सुरक्षा की मजबूत आधारशिला बनता है। जनधन, डिजिटल भुगतान, यूपीआई और औपचारिक अर्थव्यवस्था के विस्तार ने नागरिक को अधिक वित्तीय रूप से जागरूक बनाया है। आज करदाता केवल कर अदा करने वाला नहीं, बल्कि आर्थिक अनुशासन का प्रतिनिधि है। विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ती वित्तीय साक्षरता इसी परिवर्तन का संकेत है। नई पीढ़ी जब कर को दंड नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व मानेगी, तभी आर्थिक राष्ट्रवाद विचार नहीं, व्यवहार बनेगा।

कर नीति अब केवल आय का साधन नहीं, आने वाले भारत की दिशा तय करने का माध्यम भी है। स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हरित निवेश, टिकाऊ उद्योग और ऊर्जा-दक्ष तकनीकों को प्रोत्साहन इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौती के बीच भारत ने नेट-ज़ीरो उत्सर्जन सहित अनेक दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ऐसे में कर व्यवस्था केवल आर्थिक गतिविधियों को नहीं, बल्कि पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली को भी गति दे रही है। कर प्रोत्साहनों से उद्योग और नागरिक हरित विकल्प अपनाते हैं, तो उसका लाभ वर्तमान से आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचता है। इस प्रकार आयकर व्यवस्था अब राजस्व-संग्रह से आगे बढ़कर सतत विकास की प्रभावी प्रेरक बन चुकी है।

कर व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा कर-संग्रह नहीं, कर-निष्ठा है। कर चोरी, अघोषित आय और नकद अर्थव्यवस्था का विस्तार ईमानदार करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ डालता है और सामाजिक असमानता को गहरा करता है। इसलिए प्रभावी कर प्रशासन और करदाता-सुविधा के बीच संतुलन अनिवार्य है। सरकार की जिम्मेदारी सरल कानून, स्पष्ट प्रक्रियाएँ और त्वरित शिकायत निवारण सुनिश्चित करना है, वहीं नागरिकों को समझना होगा कि कर से बचना अंततः राष्ट्र और अपने ही विकास से विमुख होना है। लोकतंत्र केवल अधिकारों का उत्सव नहीं, दायित्वों का अनुशासन भी है। जब कर भुगतान राष्ट्रनिर्माण में स्वैच्छिक सहभागिता का संस्कार बन जाएगा, तब अनुपालन दंड के भय से नहीं, जागरूक नागरिकता से स्वतः सुनिश्चित होगा।

विश्व में भारत के खिलाफ नैरेटिव गढ़ता बीबीसी

संजय सक्सेना
लखनऊ,उत्तरप्रदेश

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

दुनिया भर में अपनी पत्रकारिता के कारण सुर्खियों में रहने वाला बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन) का विवादों से गहरा नाता रहा है। कई देश बीबीसी की खबरों को उसके 'एजेंडे' के रूप में देखते हैं। बीबीसी पर भारतीय राजनीति, समाज और नीति-निर्माण को प्रभावित करने के लिए एजेंडा-आधारित पत्रकारिता और नैरेटिव मैनिपुलेशन (कहानियों को तोड़ने-मरोड़ने) के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। आलोचकों, विचारकों और भारत सरकार के समर्थकों का मानना है कि बीबीसी अक्सर भारत की नकारात्मक छवि पेश करता है और संवेदनशील मुद्दों पर एकतरफा दृष्टिकोण अपनाकर असंतोष को भड़काता है। ऐसा ही कुछ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान भी देखने को मिल रहा है।बीबीसी की रिपोर्टिंग पर नज़र डालने से कुछ विशेष पैटर्न सामने आते हैं, जिनके जरिए खबरों को एक खास दिशा दी जाती है। भारत से जुड़ी खबरों में ऐसे शीर्षकों का चयन किया जाता है, जो सीधे तौर पर देश की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। जटिल सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को सरलीकृत करके सीधे तौर पर बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक के रूप में पेश किया जाना। बीबीसी का लोकल नैरेटिव को ग्लोबल एजेंडा बनाना भी अक्सर चिंताजनक नजर आता है। उसके द्वारा स्थानीय स्तर के आपराधिक मामलों को राष्ट्रीय राजनीति और सरकार की नीतियों से जोड़कर दिखाने के कई उदाहरण मौजूद हैं। बीबीसी द्वारा अपनी रिपोर्ट में केवल उन्हीं विचारकों, पत्रकारों या कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाता है, जो सरकार विरोधी रुख रखते हैं। बीबीसी की दखलअंदाजी और मैनिपुलेशन के कई उदाहरण मौजूद हैं।बीबीसी द्वारा 2023 में दो भागों में जारी की गई 'इंडिया- द मोदी क्वेश्चन' डॉक्यूमेंट्री में 2002 के गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। इस डॉक्यूमेंट्री को ऐसे समय पर रिलीज किया गया, जब भारत जी-20 (जी-20) की अध्यक्षता संभाल रहा था और वैश्विक मंच पर अपनी छवि मजबूत कर रहा था। इसमें भारत की सर्वोच्च अदालत द्वारा गठित एसआईटी की उस जांच को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया, जिसने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी। दरअसल, बीबीसी का उद्देश्य कानूनी रूप से सुलझ चुके इस संवेदनशील और ध्रुवीकरण करने वाले मुद्दे को दोबारा हवा देकर देश में राजनीतिक अस्थिरता और असंतोष पैदा करना था। साल 2020-2021 में भारत सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान बीबीसी की कवरेज को बेहद एकतरफा माना गया। बीबीसी की ग्राउंड रिपोर्ट्स और डिजिटल आर्टिकल्स में मुख्य रूप से आंदोलनकारियों के पक्ष को ही सही ठहराया गया। इसमें लाल किले पर हुई हिंसा और पुलिसकर्मियों पर हुए हमलों को या तो बहुत कम दिखाया गया या उन्हें जायज ठहराने की कोशिश की गई। कानूनों के समर्थन में खड़े करोड़ों छोटे किसानों के दृष्टिकोण को बीबीसी ने अपनी मुख्यधारा की कहानियों में कोई जगह नहीं दी। इस कवरेज ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश दिया कि भारत सरकार किसानों का दमन कर रही है, जिससे भारत की लोकतांत्रिक साख को चोट पहुंची।

2020 में समान नागरिक संहिता यानी सीएए विरोधी प्रदर्शनों और उसके बाद फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान बीबीसी की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे। बीबीसी ने सीएए को एक मुस्लिम विरोधी कानून के रूप में प्रचारित किया, जबकि यह कानून केवल पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए था, न कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए। दिल्ली दंगों की रिपोर्टिंग में बीबीसी ने हिंसा को एकतरफा मुस्लिम विरोधी दंगे के रूप में पेश किया, जबकि दंगों में दोनों पक्षों (हिंदू और मुस्लिम) के लोग मारे गए थे और खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा व पुलिस हेड कांस्टेबल रतन लाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बीबीसी की इस तरह की रिपोर्टिंग ने देश के भीतर सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ाने और विदेशों में भारत की छवि को एक असहिष्णु देश के रूप में पेश करने का काम किया।1947 से लेकर अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने तक, बीबीसी की कश्मीर नीति को लेकर भारत में हमेशा आक्रोश रहा। बीबीसी अपनी रिपोर्टों में कश्मीर को भारत प्रशासित कश्मीर लिखता रहा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद बीबीसी ने घाटी में केवल तालाबंदी, विरोध और सेना की कथित ज्यादतियों को ही दिखाया। वहां आतंकवाद के खात्मे, विकास कार्यों, स्कूलों के खुलने और कश्मीरी पंडितों के दर्द को उसकी रिपोर्टिंग में हमेशा हाशिए पर रखा गया। उसकी यह रिपोर्टिंग वैश्विक स्तर पर कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने और पाकिस्तान के रुख को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा गया।2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान बीबीसी की कवरेज मानवीय संकट से ज्यादा राजनीतिक प्रहार पर केंद्रित थी। बीबीसी ने श्मशान घाटों और जलती हुई चिताओं की तस्वीरों को अत्यधिक ड्रोन कैमरों के जरिए ज़ूम करके दिखाया। जबकि पश्चिमी देशों (जैसे अमेरिका और यूके) में महामारी से भीषण मौतें होने के बावजूद वहां के मीडिया ने लाशों और कब्रिस्तानों की ऐसी डरावनी तस्वीरें नहीं दिखाईं। आपदा के समय इस तरह के दृश्य बार-बार दिखाकर बीबीसी ने देश के भीतर जनता में पैनिक (डर का माहौल) पैदा किया और सरकार की व्यवस्था को पूरी तरह से विफल दिखाने का प्रयास किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि बीबीसी का यह रवैया महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरे निहित स्वार्थ थे। संवेदनशील मुद्दों को भड़काना, तथ्यों को आधा-अधूरा पेश करना और भारत की नकारात्मक छवि को दुनिया के सामने बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना इसकी कार्यशैली का हिस्सा रहा है।

बीबीसी की रिपोर्टिंग पर नज़र डालने से कुछ विशेष पैटर्न सामने आते हैं, जिनके जरिए खबरों को एक खास दिशा दी जाती है। उसके द्वारा भारत से जुड़ी खबरों में ऐसे शीर्षकों का चयन किया जाता है, जो सीधे तौर पर देश की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। बीबीसी बेहद आसानी से जटिल सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को सरलीकृत करके सीधे तौर पर बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक के रूप में पेश करके देश में टकराव की स्थिति पैदा करने से चूकता नहीं है। इसी तरह से स्थानीय स्तर के आपराधिक मामलों को राष्ट्रीय राजनीति और सरकार की नीतियों से जोड़कर दिखाया जाता है। बीबीसी के ताजा एजेंडे की बात की जाए तो अबकी उसने भारत के कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन को शुरुआत से ही एक बड़े और सुनियोजित तरीके से कवर किया है। आलोचकों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक डिजिटल मजाक या सैटायर (व्यंग्य) के रूप में शुरू हुए इस अभियान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी विरोधी नैरेटिव में बदलने के पीछे बीबीसी की रिपोर्टिंग का बड़ा हाथ रहा है। बीबीसी ने जिस तरह से इस आंदोलन को हवा दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उनकी सरकार के खिलाफ नैरेटिव तैयार किया, उसके मुख्य बिंदु और तरीके की बात की जाए तो उसके द्वारा कॉकरोच जनता पार्टी के डिजिटल व्यंग्य को वैश्विक जन-विद्रोह के रूप में प्रोजेक्ट करना बीबीसी की बड़ी चाल थी। शुरुआत में अभिजीत दिपके द्वारा बनाई गई कॉकरोच जनता पार्टी केवल एक मजाकिया सोशल मीडिया पेज था,जिसके सदस्यता मानदंडों में बेरोजगार होना,आलसी होना और प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालना शामिल था। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट्स में बार-बार इस बात पर जोर दिया कि सीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या भाजपा से भी आगे निकल गई है, जिससे वैश्विक स्तर पर यह संदेश गया कि मोदी सरकार अपनी लोकप्रियता पूरी तरह खो चुकी है। यह आंदोलन मूल रूप से नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक और उसमें सुधार की जायज मांगों को लेकर जमीन पर उतरा था, लेकिन बीबीसी ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स और वीडियो पैकेज में इसे केवल एक परीक्षा प्रणाली या प्रशासनिक विफलता के रूप में नहीं दिखाया। बीबीसी की रिपोर्टिंग ने इसे सीधे पीएम मोदी की नीतियों और 12 साल के शासनकाल के खिलाफ एक सीधे राजनीतिक खतरे के रूप में पेश किया। बीबीसी के संवाददाताओं ने बार-बार यह नैरेटिव गढ़ा कि मोदी सरकार युवाओं की आवाज को दबा रही है और देश में प्रेस स्वतंत्रता व नागरिक स्वतंत्रता लगातार गिर रही है। 20 जुलाई 2026 को जब संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और दिल्ली पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुईं, तो कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। इसे बीबीसी ने अपनी हेडलाइंस और वीडियो में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को क्रूर और बर्बर क्रैकडाउन के रूप में बार-बार उछाला। बीबीसी ने इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया या बहुत कम महत्व दिया कि इस हिंसा में 100 से अधिक पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। जलते हुए तंबू और आंसू गैस के दृश्यों को इस तरह दिखाया गया, जैसे कि भारत में कोई अलोकतांत्रिक शासन चल रहा हो। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दल इस आंदोलन के समर्थन में आए और प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया, तो बीबीसी ने इसे सरकार के लिए बढ़ते दबाव और संकट के रूप में प्रचारित किया।

जंतर-मंतर,राजनीति और जन-आक्रोश का यह ताना-बाना बेहद जटिल है...

डॉ. मुश्ताक़ अहमद शाह सहज,हरदा,मध्य प्रदेश

दिल्ली का ऐतिहासिक जंतर-मंतर केवल पत्थरों और चौराहों का एक भूभाग मात्र नहीं है,बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की अंतरात्मा का वह मुखर केंद्र है जहाँ सदियों से उपेक्षित,पीडित और अधिकारों से वंचित आम नागरिक अपनी उम्मीदों की आख़िरी आस लेकर पहुंचता है। आज जब इस पावन स्थल पर गूंजने वाले आंदोलनों और प्रदर्शनों का गहराई से विश्लेषण किया जाता है, तो सबसे पहले यह सवाल उठता है कि क्या ये पूरी तरह से राजनीतिक लाभ से प्रेरित होते हैं? इस पर यथार्थ यह है कि राजनीति और जन-आक्रोश का यह ताना-बाना बेहद जटिल है,जहाँ एक ओर कुछ अवसरों पर राजनीतिक दल अपनी ज़मीन मज़बूत करने या चुनावी रोटियां सेकने के लिए ऐसे मंचों का परोक्ष या अपरोक्ष उपयोग करते हैं, वहीं दूसरी ओर इन प्रदर्शनों की मूल आत्मा अक्सर उन भीषण वास्तविकताओं,जैसे बेरोजगारी के दलदल में धंसता युवा, महंगाई से त्रस्त गृहणियां, न्याय के लिए दर-दर भटकते किसान और शोषण का शिकार शोषित वर्ग,से उपजी होती है, जिनका किसी राजनीतिक एजेंडे से कोई सरोकार नहीं होता। इसके बावजूद, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब इन जायज़ और ज़मीनी मुद्दों को लेकर जनता सड़कों पर उतरती है, तो हमारा शासन-प्रशासन और कार्यपालिका जवाबदेही से बुरी तरह कतराने लगते हैं, अधिकारी और नीति-निर्माता राजनीतिक आक़ाओं के दबाव में जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के बजाय फ़ाइलों के जाल,लालफ़ीताशाही और टालमटोल की नीतियों के पीछे छिप जाते हैं। संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन,सभा करने और अपने विचार व्यक्त करने का पावन अधिकार देता है, जिसका अर्थ है कि जब तक विरोध प्रदर्शन अनुशासित और अहिंसक हैं, तब तक वे पूरी तरह से कानूनी और संवैधानिक दायरे के भीतर आते हैं, और उन्हें कभी भी गैर-कानूनी या राष्ट्र विरोधी क़रार नहीं दिया जा सकता। परंतु वर्तमान व्यवस्था का यह सबसे काला पहलू है कि जब नागरिक अपने बुनियादी हक़ और न्याय की भीख मांगते हैं,तो क़ानून-व्यवस्था और शांति स्थापना के नाम पर पुलिस प्रशासन द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग, बेरहम लाठीचार्ज और मनमाने ढंग से की जाने वाली गिरफ़्तारियों का सहारा लिया जाता है,क्या अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना कोई ऐसा अपराध है जिसके लिए नागरिकों को दमन का सामना करना पड़े? जब समाज के एक बड़े और मुख़र वर्ग का यह दर्द सड़कों पर जन-आंदोलन का रूप ले लेता है, तब उसे देश की सामूहिक आवाज़ मानने के बजाय सरकार द्वारा साधी जाने वाली लंबी और गहरी चुप्पी न केवल लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों की गला घोंटने जैसी है, बल्कि यह सत्ता और आम जनमानस के बीच की खाई को और अधिक चौड़ा करती है। एक स्वस्थ, जीवंत और परिपक्व लोकतंत्र की सबसे बड़ी शर्त यह होती है कि वह अपने नागरिकों के असंतोष को सुने, उसकी तह तक जाकर समाधान ढूंढे और प्रशासन को पूरी तरह जवाबदेह बनाए,क्योंकि संवादहीनता, अहंकार और दमन की नीतियों से कभी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सकता,बल्कि इससे जनता का संवैधानिक व्यवस्था से धीरे-धीरे विश्वास उठने लगता है जो राष्ट्रहित में कतई उचित नहीं है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

CMYK

राहुल गांधी के विरोध में भाजयुमो का धरना,पुतला दहन कर जताया आक्रोश

घड़ी चौक पर प्रदर्शन,कांग्रेस पर अराजक राजनीति का आरोप,लोकतांत्रिक मर्यादाओं की रक्षा का लिया संकल्प

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान एवं भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) सरगुजा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास के घेराव के विरोध में बुधवार को स्थानीय घड़ी चौक पर धरना-प्रदर्शन किया तथा उनका पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजयुमो जिलाध्यक्ष निशांत सिंह सोलू ने किया। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री विनोद हर्ष, जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन शुक्ला सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। धरना को संबोधित करते हुए भाजपा जिला महामंत्री विनोद हर्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का प्रयोग, निराधार आरोप और प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत है। उनका कहना था कि कांग्रेस युवाओं के मुद्दों को राजनीतिक रंग देकर भ्रम फैलाने का

प्रयास कर रही है,जबकि भाजपा हमेशा लोकतांत्रिक एवं मर्यादित राजनीति में विश्वास रखती है। जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन शुक्ला ने कहा कि बिना पूर्व सूचना प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करना राहुल गांधी की राजनीतिक उच्छृंखलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि देश की जनता संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करती है तथा अराजकता की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी। भाजपा उपाध्यक्ष मधु चौदाहा ने कहा कि कांग्रेस जनता के वास्तविक मुद्दों से भटककर केवल राजनीतिक नौटंकी करने में लगी हुई है। वहीं विकास पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि कांग्रेस भ्रम और विरोध की राजनीति कर रही है। निलेश सिंह ने कहा कि युवाओं का भविष्य सकारात्मक राजनीति और विकास से सुरक्षित होगा, जबकि वैभव सिंह देव ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन उसकी भी संवैधानिक मर्यादा होती है और कांग्रेस लगातार उसका उल्लंघन कर रही है। मंडल अध्यक्ष कमलेश तिवारी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध हैं और कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते रहेंगे। वहीं भाजयुमो जिलाध्यक्ष निशांत सिंह सोलू ने कहा कि युवा मोर्चा देश, लोकतंत्र और संविधान के सम्मान के लिए हमेशा खड़ा रहेगा तथा राहुल गांधी का यह कदम निंदनीय है।

कार्यक्रम का संचालन अनीश सिंह ने किया, जबकि अविनाश मंडल ने आभार व्यक्त किया। धरना-प्रदर्शन में निश्चल प्रताप सिंह, रुपेश दुबे, शुभांगी बिहाड़े, प्रियंका चौबे, नीलम राजवाड़े, सरस्वती यादव, नलिनी पांडे, राखी यादव, संगीता सोनी, नंदनी सिंह, मीरा तिवारी, रीना राय, गुंजन सिंह देव, संजीव वर्मा, विकास शुक्ला, दीपक यादव, शुभम अंबष्ट, अभिषेक सिंह पिंटी, आशुमल गर्ग, रवजोत सिंह, ओंकारेश्वर सिंह, अनुराग शुक्ला, प्रीतेश दुबे, अभिषेक माथुर, आनंद साहू, प्रिंस तिवारी, सुधांशु चौबे, आयुष दुबे, विशाल सिंह, रोहन मंडल सहित बड़ी संख्या में भाजपा एवं भाजयुमो कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

राजपुर ब्लॉक कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों पर दर्ज प्रकरण वापस लेने की उठाई मांग

-संवाददाता-
राजपुर,23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आई कथित अनियमितताओं एवं शिक्षा व्यवस्था की खामियों के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राजपुर ने मंगलवार को प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम का नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीरज तिवारी ने किया। ज्ञापन में कांग्रेस ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने,कथित अनियमितताओं के दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने, शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं के लिए जवाबदेही तय करने तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दर्ज सभी प्रकरण वापस लेने की मांग की। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि कांग्रेस विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व विधायक डॉ. प्रीतम राम, जिला लघुवनोपज समिति

अध्यक्ष लालसाय मिंज, किसान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राम बिहारी यादव, किसान कांग्रेस प्रदेश महासचिव बृजेश मिश्रा, मंडल अध्यक्ष सतेंद्र पाण्डेय, सुनील भगत, ब्लॉक उपाध्यक्ष विद्यानंद दुबे, विकाश अंबष्ट, पीटर लकड़ा, आनंद मसीह, नूतन खलखो, लक्ष्मी सोनी, दीपिका तिर्की, नेहा चौबे, अनुराधा यादव, राजेंद्र मिश्रा, मनोज अग्रवाल, रूपेश यादव, रवि सोनी, प्रमोद ठाकुर, संजीव गुप्ता, कौशल चौबे, अमीन साय, आलोक सिंह, पंकज ठाकुर, सरजू लकड़ा, लुकेश यादव, श्याम दास, अविनाश तिग्गा, सुशील पैकरा, अनिल यादव, सोहर एक्का, अखिल श्रीवास्तव, नारद सिंह, रूप नारायण सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नीट अभ्यर्थी हरिका राव नायडू को कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि,निकाली मौन रैली

राजीव भवन से गांधी प्रतिमा तक कैंडल मार्च,परीक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

बस्तर की नीट अभ्यर्थी हरिका राव नायडू के निधन पर जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने गुरुवार को राजीव भवन से गांधी प्रतिमा तक मौन रैली निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। रैली के बाद कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मोमबत्तियां जलाकर दिवंगत छात्रा को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हरिका राव नायडू ने नीट की पहली परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए थे और चयन को लेकर आश्वस्त थीं,लेकिन पेपर लीक के बाद दोबारा आयोजित परीक्षा में असफल होने से वह मानसिक तनाव में आ गईं। कांग्रेस ने इस घटना को शिक्षा एवं परीक्षा व्यवस्था की गंभीर विफलता बताते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग की। इस अवसर पर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सीमा सोनी ने कहा कि केंद्र सरकार की परीक्षा प्रणाली की विफलता के कारण एक प्रतिभाशाली छात्रा की जान चली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि सरकार परीक्षाओं का निष्पक्ष संचालन नहीं कर सकती तो उसे नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ देना चाहिए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जे.पी.

श्रीवास्तव, द्वितेंद्र मिश्रा, राकेश गुप्ता, हेमंत सिन्हा, विनय शर्मा, नुरुल अमीन सिद्दीकी, दुर्गेश गुप्ता, मदन जायसवाल, प्रशांत सिंह, इंद्रजीत सिंह धंजल, अनिमा केरकेट्टा, संजीव मंदिलवार, मुनेश्वर राजवाड़े, शैलेन्द्र प्रताप सिंह, संजय सिंह, जमील खान, आलोक सिंह, नरेंद्र विश्वकर्मा, चंद्रप्रकाश सिंह, रजनीश सिंह, निकी खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मानसून ने लौटाई सरगुजा की रौनक,डेम लबालब मैनपाट गुलजार,खेतों में बढ़ी चहल-पहल...

तीन दिन की लगातार बारिश से घुटघुट्ठा डेम के खुले दो गेट,मैनपाट बादलों की आगोश में, किसानों ने तेज की धान रोपाई

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

करीब एक महीने तक कमजोर पड़े मानसून ने आखिरकार सरगुजा में दमदार वापसी कर ली है। पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जिले की तस्वीर बदल दी है। सूखे जैसे हालात से जूझ रहे खेत अब पानी से भर गए हैं, घुटघुट्ठा डेम लबालब होकर छलकने लगा है और मैनपाट की वादियां बादलों व धुंध से ढंक गई हैं। बारिश ने जहां किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है,वहीं पर्यटन कारोबार में भी नई उम्मीद जगा दी है। लगातार वर्षा के कारण घुटघुट्ठा डेम का जलस्तर तेजी से बढ़ा। मंगलवार तक 81 प्रतिशत भरा डेम बुधवार को 90 प्रतिशत से अधिक भर गया। इसके बाद जल संसाधन विभाग ने अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए दो गेट खोल दिए। डेम से पानी छोड़े जाने के बाद घुटघुट्ठा नदी का बहाव तेज हो गया है। विभाग ने नदी किनारे रहने वाले लोगों और मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी है। यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो अन्य गेट भी खोले जा सकते हैं।

बादलों के बीच फिर खिल उठा मैनपाट : बारिश ने सरगुजा के पर्यटन स्थल मैनपाट की खूबसूरती को नई पहचान दी है। बादल पहाड़ियों से उतरकर सड़कों तक पहुंच रहे हैं। चारों ओर फैली हरियाली, बहते झरने

और ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। सप्ताहांत से पहले ही पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। होटल और रिसॉर्ट संचालकों को भी आने वाले दिनों में बेहतर कारोबार की उम्मीद है।

खेतों में लौट आई रौनक : बारिश का सबसे बड़ा फायदा खेती-किसानी को मिला है। अब तक पर्याप्त बारिश नहीं होने से धान की रोपाई पिछड़ रही थी, लेकिन तीन दिन की लगातार वर्षा ने खेतों में पर्याप्त पानी पहुंचा दिया है। गांवों में किसान परिवार सहित रोपाई में जुट गए हैं। महिलाओं की टोली खेतों में धान रोप रही है, जबकि पुरुष खेतों की तैयारी और पानी की व्यवस्था संभाल रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रही तो अधिकांश क्षेत्र में समय पर रोपाई पूरी हो जाएगी।

102 मिमी बारिश से बदला मौसम

अंबिकापुर में पिछले 24 घंटे के दौरान 102 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश से तापमान में गिरावट आई है और उमस से लोगों को राहत मिली है। हालांकि कई ग्रामीण इलाकों में पुल-पुलियों के ऊपर पानी बहने से आवागमन प्रभावित हुआ है।

घटने लगी बारिश की कमी

इस मानसून सीजन में अब तक सरगुजा जिले में सामान्य से करीब 58 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई थी, जिससे किसान चिंतित थे। लेकिन पिछले तीन दिनों की अच्छी बारिश ने कमी की भरपाई की उम्मीद जगा दी है। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक उत्तर छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। प्रशासन ने नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील की है।

विकास शुक्ल 'चंदन' बने भाजयुमो के बलरामपुर-रामानुजगंज जिला प्रभारी

प्रदेश नेतृत्व ने की नियुक्ति, संगठन को और मजबूत करने की जताई उम्मीद

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव एवं प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी की सहमति से भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा ने संभाग एवं जिला प्रभारियों की घोषणा की है। इसके तहत विकास शुक्ल 'चंदन' को सरगुजा संभाग के अंतर्गत बलरामपुर-रामानुजगंज जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है। विकास शुक्ल 'चंदन' लंबे समय से भारतीय जनता युवा मोर्चा में सक्रिय हैं। वर्तमान में वे भाजयुमो की प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश आईटी प्रमुख के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। इससे पहले वे जिला उपाध्यक्ष,जिला मंत्री,नगर प्रशिक्षण प्रमुख और नगर कार्यसमिति सदस्य सहित संगठन के विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। पार्टी ने उनकी संगठनात्मक सक्रियता, कार्यकुशलता और लंबे अनुभव को देखते हुए यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उनकी नियुक्ति पर भाजपा एवं भाजयुमो के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में संगठन और अधिक सशक्त होगा। नियुक्ति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विकास शुक्ल 'चंदन' ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि संगठन ने जिस विश्वास के साथ उन्हें यह दायित्व सौंपा है, उस पर वे पूरी निष्ठा, समर्पण और कार्यकर्ता भावना के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे तथा संगठन को मजबूत बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे।

बस से गिरने से कंडेक्टर की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

चालक द्वारा अचानक बस आगे बढ़ाने से केबिन में सामान बांध रहा कंडेक्टर गिर गया, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक,कोतवाली थाना अंतर्गत रिंग रोड नमनाकला निवासी शैलेन्द्र दुबे पिता विजय कांत दुबे 41 वर्ष, गुप्ता बस में कंडेक्टर का काम करता था। 22 जुलाई को वह अंबिकापुर से गढ़वा जाने वाली बस के केबिन में चढ़कर दोपहर करीब 1.15 बजे कुछ सामान बांध रहा था। इसी दौरान अचानक चालक बस को आगे बढ़ाया,जिससे कंडेक्टर का संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर गया। घटना में उसे सिर में गंभीर चोटें आई थी। बस चालक व अन्य लोगों की मदद से उसे ऑटो में मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल भेजा गया।

प्रतिबंधित ई-सिगरेट बेचने वाला दुकानदार गिरफ्तार,55 हजार रुपये का माल जब्त

गांधीनगर पुलिस की कार्रवाई, 35 ई-सिगरेट व 3 हजार रुपये नकद बरामद

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (ई-सिगरेट/वेप) की अवैध बिक्री के खिलाफ गांधीनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पान दुकान संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 35 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और बिक्री से संबंधित 3 हजार रुपये नकद सहित करीब 55,500 रुपये का मशरुका जब्त किया है। पुलिस के अनुसार, डीआईजी एवं एसएसपी राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में थाना गांधीनगर पुलिस टीम 21 जुलाई को सुभाषनगर-बनारस रोड

क्षेत्र में गश्त एवं अपराधियों की तलाश में निकली थी।

इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आयुषी डेली निड्स (पान कॉर्नर) का संचालक प्रतिबंधित ई-सिगरेट का अवैध भंडारण एवं विक्रय कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने दुकान पर दबिश दी। तलाशी के दौरान दुकान से 35 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट तथा 3 हजार रुपये नकद बरामद किए गए। पूछताछ में संचालक प्रांशु केसरी (24 वर्ष) निवासी वार्ड क्रमांक-10, बनारस रोड, गांधीनगर, प्रतिबंधित सामग्री के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम, 2019 की धारा 7 एवं 8 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 466/2026 दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। पुलिस की इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, उपनिरीक्षक दिलीप दुबे, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक भारतीय मार्कण्डेय, सहायक उपनिरीक्षक विवेक चंद्राकर एवं वरदान लकड़ा की सक्रिय भूमिका रही।

जमीन दिलाने का झांसा देकर 2 लाख 61 हजार रुपए की ठगी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

अपना घर बनाने का सपना देख रहे एक राजमिस्त्री को जनरल श्रेणी की जमीन दिलाने का झांसा देकर 2 लाख 61 हजार रुपए की ठगी कर ली गई। आरोपियों ने कम कीमत में जमीन दिलाने का भरोसा दिलाया, लेकिन बाद में पता चला कि जिस जमीन का सौदा कराया जा रहा था, वह अनुसूचित जनजाति वर्ग की है और उसकी रजिस्ट्री संभव नहीं है। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मूल रूप से झारखंड के गढ़वा जिले के मानपुर निवासी इसफाक अंसारी पिछले तीन वर्षों से अंबिकापुर में रहकर राजमिस्त्री का काम कर रहा है। वह तकिया क्षेत्र में किराए के मकान में परिवार के साथ रहता है। इसी दौरान परिचित रमजान अंसारी ने उसे कम कीमत में जनरल श्रेणी की जमीन दिलाने का भरोसा दिया। उसने 2 से 3 डिसमिल जमीन खरीदने की इच्छा जताई,जिस पर आरोपियों ने 6.15 लाख रुपए में तीन डिसमिल जमीन दिलाने का प्रस्ताव रखा। पीड़ित का आरोप है कि रमजान अंसारी, उसकी पत्नी शमीमा बीबी,साला हसीब तथा अन्य आरोपियों ने विश्वास में लेकर उससे अग्रिम राशि के रूप में 2 लाख 61 हजार रुपए और 11 हजार रुपए एग्रीमेंट के नाम पर ले लिए। बाद में जानकारी मिली कि संबंधित जमीन अनुसूचित जनजाति वर्ग की है,जिसकी रजिस्ट्री उसके नाम नहीं हो सकती। जब पीड़ित ने रुपए वापस मांगे तो आरोपियों ने कथित रूप से जान से मारने की धमकी दी।

मोबाइल पर लिंक को खोलते ही कट गए 1.33 लाख रुपए

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

मोबाइल में बैंक खाता को अपडेट करते व्यवसायी 1 लाख 33 हजार रुपये की ठगी का शिकार हो गया। चोपड़ापारा निवासी व्यवसायी पूरन अग्रवाल ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है कि, उनका युनियन बैंक अंबिकापुर सीसी लीमिट खाता है। बीते 10-15 दिनों से उनके मोबाइल में अपडेट का संदेश आ रहा था। 20 जुलाई को एक मोबाइल नंबर धारक ने व्हाट्सअप मैसेज करके शाम 7.30 बजे एक लिंक भेजा, जिसमें युनियन बैंक का लोगों लगा हुआ था। जैसे मैं उन्होंने लिंक को अपडेट किया खाता से 1 लाख 33 हजार रुपये कटने का मैसेज आया। खाता से उक्त रकम पूरन अग्रवाल को आईएमपीएस के माध्यम से ट्रांसफर करना बताया गया था। व्यवसायी का कहना है कि, उनके द्वारा न ही कोई ट्रांजेक्शन किया गया है और ना ही वे पूरब अग्रवाल को जानते हैं। खाते से तकनीकी धोखाधड़ी रकम निकालने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

मकान में अवैध अंग्रेजी शराब बेच रहा आरोपी गिरफ्तार,15.755 लीटर शराब जब्त

गांधीनगर पुलिस की कार्रवाई,7180 रुपये कीमत की शराब बरामद

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए गांधीनगर पुलिस ने अवैध रूप से अंग्रेजी शराब का भंडारण एवं बिक्री कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 15 लीटर 755 मिलीलीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 7,180 रुपये बताई गई है। पुलिस के अनुसार, डीआईजी एवं एसएसपी राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में जिले

में आबकारी अधिनियम के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 21 जुलाई को गांधीनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नवापारा गोधनपुर रोड निवासी एक व्यक्ति अपने मकान में बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब रखकर अवैध बिक्री कर रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी।

वहां रविन्द्र सिंह (44 वर्ष) निवासी नवापारा गोधनपुर रोड, थाना गांधीनगर मिला। पूछताछ के दौरान उसके घर से विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब और बीयर बरामद की गई। बरामद शराब में 8 बोतल सिम्बा बीयर, 5 बोतल हंटर बीयर, 5 बोतल ड्रंक 10000 बीयर, 4 सिम्बा कैन बीयर, 7 बोतल रॉयल चैलेंज व्हिस्की तथा 1 बोतल गोवा स्पेशल व्हिस्की शामिल है। कुल 15 लीटर 755 मिलीलीटर शराब की कीमत 7,180 रुपये आंकी गई है। आरोपी से शराब रखने एवं बिक्री के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई अनुमति या लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 468/2026 के तहत आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

C M Y K

54 साल पुराना स्कूल,टपकती छत और रिसती दीवारें,जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर सोनहत के नौनिहाल

1970 में बना स्कूल अब खुद सहारे की तलाश में,बारिश में कक्षाएं बनीं तालाब,छत से झड़ रहा प्लास्टर,कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

शिक्षा के मंदिर की बदहाल तस्वीर,जर्जर स्कूल में मौत के साये तले पढ़ रहे छात्र

1970 में बना स्कूल अब खुद सहारे का मोहताज,बारिश में कक्षाएं बनीं तालाब

सोनहत का 54 साल पुराना स्कूल बना हादसे का इंतजार,छत टपकी तो एक कोने में सिमटे छात्र

करोड़ों की शिक्षा योजनाएं,लेकिन स्कूल की छत से टपक रहा पानी

जर्जर भवन में चल रही पढ़ाई, हर बारिश के साथ बढ़ रहा हादसे का खतरा

बच्चों की पढ़ाई या जान से खिलवाड़? 54 साल पुराने स्कूल की भयावह हकीकत

कहीं देर न हो जाए...जर्जर स्कूल भवन में हर दिन हादसे के साये में शिक्षा

-राजन पाण्डेय-

सोनहत,23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च करने का दावा करती हैं,स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा,नई शिक्षा नीति और गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना जैसे बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं,लेकिन कोरिया जिले के दूरस्थ आदिवासी विकासखंड सोनहत स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थिति इन सभी दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। वर्ष 1970 में स्थापित यह विद्यालय आज 54 वर्ष पुराने जर्जर भवन में संचालित हो रहा है,जहां छात्र-छात्राएं हर दिन पढ़ाई से पहले अपनी सुरक्षा की चिंता करने को मजबूर हैं,बरसात शुरू होते ही विद्यालय की हालत इतनी खराब हो जाती है कि कई कक्षाएं पानी से भर जाती हैं,छत से लगातार पानी टपकता रहता है और दीवारों से सीलन के साथ प्लास्टर झड़ने लगता है, इसके बावजूद सैकड़ों छात्र-छात्राएं इसी भवन में बैठकर पढ़ाई करने को विवश हैं।

क्या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है?-यह पहला अवसर नहीं है जब किसी सरकारी स्कूल की जर्जर स्थिति चर्चा में आई हो,प्रदेश में पहले भी कई स्थानों पर स्कूल भवनों की छत गिरने,दीवार ढहने और प्लास्टर गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं,ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या प्रशासन किसी दुर्घटना के बाद ही जागेगा? क्या बच्चों की सुरक्षा केवल कागजों तक सीमित रह गई है?

54 साल पुराना भवन अब जवाब दे रहा है-वर्ष 1970 में बने इस विद्यालय ने कई पीढ़ियों को शिक्षा दी है, लेकिन समय के साथ भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है, स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से नए भवन की मांग की जा रही है,अनेक बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी सौंपे गए,इसके बावजूद आज तक कोई ठोस पहल दिखाई नहीं दी।

करोड़ों की योजनाएं,लेकिन स्कूल अब भी बदहाल-सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बजट बढ़ाने की बात करती है,स्कूलों के आधुनिकीकरण,स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के दावे किए जाते हैं,लेकिन सोनहत का यह विद्यालय उन दावों की जमीनी हकीकत बयान कर रहा है,जब बच्चों के सिर पर सुरक्षित छत ही नहीं है,तब आधुनिक शिक्षा की बातें स्थानीय लोगों को खोखली लगती हैं।

ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी-स्थानीय ग्रामीणों,अभिभावकों और विद्यार्थियों ने स्पष्ट कहा है कि यदि जल्द ही विद्यालय के लिए नए भवन की स्वीकृति नहीं दी गई अथवा तब तक सुरक्षित वैकल्पिक भवन में कक्षाओं का संचालन शुरू नहीं किया गया, तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को मजबूर होंगे,उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता।

बारिश शुरू होते ही कक्षा नहीं,तालाब बन जाता है स्कूल

मानसून की पहली अच्छी बारिश के साथ ही विद्यालय की असल तस्वीर सामने आ जाती है,कई कमरों की छतें पूरी तरह से रिसने लगती हैं,छत से गिरता पानी सीधे फर्श पर जमा हो जाता है और कुछ ही देर में पूरी कक्षा तालाब जैसी नजर आने लगती है, ऐसी स्थिति में बच्चों को अपनी बेंच-डेस्क एक कोने में खिसकाकर बैठना पड़ता है, जहां किसी तरह पानी कम टपक रहा हो,कई बार पूरी कक्षा को एक ही कोने में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है,शिक्षक भी मजबूरी में उसी स्थिति में पढ़ाई कराते हैं,क्योंकि वैकल्पिक कक्ष उपलब्ध नहीं हैं।

हर पल सिर पर मंडराता खतरा

विद्यालय भवन केवल पुराना ही नहीं,बल्कि अब बेहद जर्जर भी हो चुका है,छतों में जगह-जगह बड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं। कई स्थानों से प्लास्टर पूरी तरह झड़ चुका है,लोहे के एंगल जंग खा चुके हैं और टीन शेड भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, सबसे बड़ी चिंता यह है कि बारिश के दौरान लगातार नमी बढ़ने से भवन की मजबूती पर भी असर पड़ रहा है,शिक्षकों और अभिभावकों का कहना है कि यदि समय रहते नए भवन की व्यवस्था नहीं हुई या व्यापक मरम्मत नहीं कराई गई, तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है।

शिक्षक भी हैं परेशानी में...

समस्या केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है, विद्यालय का स्टाफ रूम भी पानी टपकने से प्रभावित है, शिक्षकों को बैठने तक के लिए सुरक्षित स्थान नहीं मिल पा रहा, विद्यालय के महत्वपूर्ण अभिलेख, परीक्षा रिकॉर्ड, अंकसूचियां, उपस्थिति रजिस्टर, प्रयोगशाला सामग्री, पुस्तकालय की पुस्तकें तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री भी पानी से खराब होने की कगार पर हैं, हर बारिश के साथ सबसे बड़ी चिंता यह रहती है कि सरकारी रिकॉर्ड कैसे सुरक्षित रखे जाएं।

पढ़ाई से ज्यादा चिंता सुरक्षा की...

विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का कहना है कि बरसात के दिनों में उनका पूरा ध्यान पढ़ाई पर नहीं रह पाता, कभी छत से पानी टपकता है,कभी प्लास्टर गिरता है तो कभी पूरी कक्षा में पानी भर जाता है, ऐसे माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना करना भी मुश्किल दिखाई देता है।

अभिभावकों में बढ़ रही बेचैनी...

बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि हर दिन बच्चों को स्कूल भेजते समय मन में डर बना रहता है, उन्हें आशंका रहती है कि कहीं अचानक छत का प्लास्टर न गिर जाए,दीवार का कोई हिस्सा न टूट जाए या पानी के कारण बिजली का कोई हादसा न हो जाए, अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी उनकी जान की सुरक्षा है।

जनता के सवाल

- क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है?
- 54 वर्ष पुराने जर्जर भवन में आखिर कब तक पढ़ेंगे छात्र?
- शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद सुरक्षित विद्यालय भवन क्यों उपलब्ध नहीं हो पा रहा?
- क्या ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की सुरक्षा शासन की प्राथमिकता में शामिल नहीं है?
- यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

अब निर्णय प्रशासन को लेना है...

सोनहत का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केवल एक जर्जर इमारत नहीं,बल्कि ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था की उपेक्षा का प्रतीक बनता जा रहा है, हर दिन सैकड़ों छात्र-छात्राएं डर और असुरक्षा के बीच पढ़ाई करने पहुंचते हैं। शिक्षक भी जोखिम उठाकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अब जरूरत केवल आश्वासनों की नहीं, बल्कि तत्काल कार्रवाई की है,या तो विद्यालय के लिए नए भवन की स्वीकृति दी जाए या तब तक सुरक्षित वैकल्पिक भवन में कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि शिक्षा का अधिकार तभी सार्थक होगा, जब विद्यालय केवल पढ़ाई का केंद्र ही नहीं, बल्कि बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान भी होगा।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप पर ग्रामीणों का फूटा आक्रोश...उपसरपंच पति पर पॉक्सो में केस

करीब 100 ग्रामीण व परिजन देर रात पहुंचे कोतवाली,तत्काल गिरफ्तारी की मांग,आरोपी फरार,पुलिस टीम दबिश में जुटी

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

नाबालिग आदिवासी छात्रा से दुष्कर्म के आरोप के बाद ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। बुधवार रात करीब 100 ग्रामीण और पीड़िता के परिजन कोतवाली पहुंचे तथा आरोपी उपसरपंच के पति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धाराओं 4 और 6 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी घटना के बाद से फरार है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता कक्षा सातवीं की छात्रा है और गांव की उपसरपंच के घर सुबह-शाम घरेलू काम करने जाती थी। दिन में वह स्कूल में पढ़ाई करती थी। परिजनों का आरोप है कि 20 जुलाई की शाम वह काम पर गई थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी। परिवार की ओर से उसे बुलाने के लिए उसकी बहन को भेजा गया, जहां बताया गया कि वह अभी काम कर रही है।

पीड़िता ने परिजनों को बताई आपबीती : परिजनों का कहना है कि देर रात घर लौटने पर छात्रा ने उनके सामने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

रिपोर्ट नहीं कराने का लगाया आरोप : पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि घटना के अगले दिन कुछ लोगों को उनके घर भेजकर समझौते का दबाव बनाया गया और रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने के बदले रुपए देने का प्रस्ताव भी रखा गया। परिजनों ने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद ग्रामीणों और रिश्तेदारों के साथ बड़ी संख्या में लोग कोतवाली पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की।

गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश

कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि साइबर सेल और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। आरोपी फिलहाल फरार है और उसे जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।

पीकअप की टक्कर से घायल युवक की मौत

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

पिकअप वाहन की ठोकर से घायल युवक की मौत हो गई। मृतक शंभुदयाल सिंह पिता सत्यनारायण सिंह 34 वर्ष,उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सरगवां का रहने वाला था। 22 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे वह अंबिकापुर स्थित मोबाइल दुकान में काम करने के लिये मोटरसायकल से आ रहा था। ग्राम सिंगीटाना में सलका मोड़ के पास सामने से आ रही पिकअप वाहन के चालक ने उसे ठोकर मार दिया। घायल अवस्था में उसे मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल भेजा गया, यहां आपातकालीन चिकित्सा परिसर में जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस मर्ग कायम कर ली है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

मिनरल फैक्ट्री की बाउंड्रीवाल से खेतों में भरा पानी,किसानों ने मांगा मुआवजा

रघुनाथपुर के ग्रामीणों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

लुंड्रा विकासखंड के रघुनाथपुर क्षेत्र के किसानों ने एक मिनरल फैक्ट्री पर बाउंड्रीवाल निर्माण से प्राकृतिक जल निकासी बाधित करने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि बारिश का पानी खेतों में भर जाने से फसल प्रभावित हो रही है। इस संबंध में ग्रामीणों ने तहसीलदार रघुनाथपुर को आवेदन सौंपकर मौके का निरीक्षण कराने,फसल नुकसान का आकलन करने तथा मुआवजा दिलाने की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि संबंधित मिनरल फैक्ट्री की बाउंड्रीवाल बनने के बाद बारिश का पानी खेतों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इससे खेती योग्य भूमि में जलभराव की स्थिति बन गई है और फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। किसानों का कहना है कि यदि शीघ्र जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो आगामी खेती भी प्रभावित होगी।

मेडिकल कॉलेज अस्पताल से मरीज गायब,परिजन परेशान

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में भर्ती एक मरीज गायब हो गया, जिससे स्वजन परेशान हैं। स्वजन ने अस्पताल के पुलिस सहायता केंद्र और मणीपुर थाना में इसकी सूचना दी है,लेकिन उसका पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक,बलरामपुर जिला के पस्ता थाना अंतर्गत ग्राम बासेन निवासी लालबिहारी रवि पिता रामनाथ रवि 40 वर्ष को बीते सोमवार की रात को अचानक झटका आने पर स्वजन राजपुर स्वास्थ्य केंद्र ले गए थे। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर करने पर मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे, यहां मेल मेडिकल वार्ड में भर्ती करके चिकित्सक उसका उपचार कर रहे थे। 22 जुलाई, बुधवार को दिन में करीब 11.30 बजे वह बेड से उठा, तो शौचालय जा रहे होंगे, सोचकर पत्नी ध्यान नहीं दी। काफी देर तक जब लालबिहारी वापस नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन शुरू हुई, और चिकित्सक, नर्स को जानकारी दी गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सीसीटीव्ही को खंगालने पर बीमार युवक अस्पताल के बीच गेट से निकलते नजर आ रहा है, लेकिन इसके बाद कहां गया,पता नहीं चल पाया है। चप्पे-चप्पे पर तैनात रहने वाले निजी सुरक्षा कर्मियों के बाद भी अस्पताल से भर्ती मरीज का गायब हो जाना समझ से परे है।

गायब युवक के स्वजन ने बताया कि, वे गृहग्राम तक गायब युवक को तलाश कर पुनः अंबिकापुर वापस लौटे हैं। मणीपुर थाना में गुम इंसान की सूचना देने के लिए वे गए थे, यहां केस दर्ज करने के लिए भर्ती पर्ची लेकर आने कहा गया। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा भी बुधवार को दोपहर तक भर्ती मरीज के गायब होने के संबंध में किसी प्रकार की तहरीर पुलिस को उपलब्ध नहीं कराई गई थी,जिससे उसकी खोजबीन की जा सके।

सूरजपुर में सनसनीखेज शिकायत

रेलवे कर्मचारी का आरोप: पुलिस के दबाव में दिए दो लाख रुपये !

जांच की मांग

महिला ने झूठे दुष्कर्म केस में फंसाने और जमीन हड़पने की दी धमकी

- 2023 में थाने बुलाकर डेढ़ लाख की वसूली का आरोप
- 2025 में फिर 50 हजार रुपये मांगने का आरोप
- ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का दावा
- बसदेई चौकी, एसपी के बाद आईजी सरगुजा से की शिकायत

क्या थाने में न्याय की जगह समझौते और वसूली का खेल ?
खाकी की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल

खाकी पर ब्लैकमेलिंग के आरोप,रेलवे कर्मचारी बोला पुलिस के डर से दिए दो लाख रुपये,अब भी मिल रही झूठे दुष्कर्म केस की धमकी

सूरजपुर में खाकी कटघरे में : महिला संग मिलीभगत कर वसूली का आरोप,ऑडियो-वीडियो लेकर आईजी पहुंचा रेलवे कर्मचारी

- क्या थाना चौकी बन गया वसूली का अड्डा...पुलिस,महिला और दो लाख की कथित उगाही की शिकायत से मचा हड़कंप
- रेलवे कर्मचारी का सनसनीखेज आरोप पुलिस के सामने दिए डेढ़ लाख,फिर भी नहीं रुकी ब्लैकमेलिंग
- खाकी पर गंभीर सवाल कार्रवाई की जगह समझौता और वसूली...आईजी से जांच की मांग
- दो लाख की कथित उगाही, झूठे दुष्कर्म केस की धमकी और पुलिस की भूमिका पर सवाल,आईजी से लगाई गुहार
- शिकायतकर्ता का दावा– ऑडियो,वीडियो और ट्रांजेक्शन सबूतों के साथ पहुंचा आईजी दरबार
- ब्लैकमेलिंग या साजिश...महिला और पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप,जांच के घेरे में सूरजपुर पुलिस
- 2023 से शुरू हुआ विवाद 2026 में पहुंचा आईजी कार्यालय,ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का दावा
- पुलिस अधीक्षक से लेकर आईजी तक पहुंची शिकायत,अब निष्पक्ष जांच सबसे बड़ा सवाल

-रामरोज खान-

सूरजपुर,23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं, कभी फरियादियों की शिकायतों पर कार्रवाई में देरी, कभी समझौते के नाम पर दबाव और कभी पुलिसकर्मियों पर पक्षपात के आरोप चर्चा का विषय बनते रहे हैं,अब सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले से सामने आया एक मामला एक बार फिर खाकी को कठघरे में खड़ा करता नजर आ रहा है,हालांकि, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि फिलहाल यह पूरा मामला शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस अधिकारियों को दिए गए आवेदन पर आधारित है और आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। ग्राम सोनपुर, तहसील भैयाथान निवासी तथा रेलवे विभाग में कार्यरत मोहम्मद कलीम अशरफ ने सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) को विस्तृत शिकायत देकर आरोप लगाया है कि वर्ष 2023 से वह एक महिला द्वारा कथित ब्लैकमेलिंग,पैसों की उगाही और झूठे दुष्कर्म प्रकरण में फंसाने की धमकियों का शिकार है, शिकायत में इससे भी अधिक गंभीर आरोप यह लगाया गया है कि पूरे घटनाक्रम के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने कानून के अनुसार कार्रवाई करने के बजाय कथित रूप से दबाव बनाकर समझौते की राह अपनाई और उसी दबाव में उससे लाखों रुपये दिलवाए गए, शिकायतकर्ता का कहना है कि अब उसके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग,वीडियो रिकॉर्डिंग तथा ऑनलाइन लेन-देन के प्रमाण मौजूद हैं, जिन्हें उसने जांच के लिए उपलब्ध कराने की बात कही है।

रिश्तेदारी से शुरू हुई पहचान, फिर विवाद में बदल गया पूरा मामला- आईजी को दिए गए आवेदन में मोहम्मद कलीम अशरफ ने बताया है कि संबंधित महिला उसके दूर के रिश्ते में मामा की लड़की लगती है,इसी कारण दोनों परिवारों के बीच वर्षों से परिचय था और समय-समय पर बातचीत भी होती थी, शिकायतकर्ता के अनुसार मई 2023 में महिला ने मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता मांगी,प्रारंभिक बातचीत सामान्य थी, लेकिन जब उससे बड़ी रकम की मांग की गई तो उसने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए पैसे देने से इंकार कर दिया, शिकायतकर्ता का आरोप है कि यहीं से पूरे विवाद की शुरुआत हुई।

मामला यहीं नहीं रुका,2025 में फिर 50 हजार रुपये वसूले जाने का आरोप- रेलवे कर्मचारी ने आवेदन में दावा किया है कि डेढ़ लाख रुपये देने के बाद भी विवाद समाप्त नहीं हुआ,उसका आरोप है कि अप्रैल 2025 में एक नगर सैनिक के माध्यम से उसे फिर पुलिस केस की धमकी देकर 50 हजार रुपये देने के लिए मजबूर किया गया, शिकायत में विस्तार से उल्लेख है कि 40 हजार रुपये नकद दिए गए, 24 अप्रैल 2025 को 5 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए,1 मई 2025 को पुनः 5 हजार रुपये ऑनलाइन भेजे गए, आवेदन में फोनपे के माध्यम से किए गए ट्रांजेक्शन और संबंधित मोबाइल नंबर का भी उल्लेख किया गया है, यदि यह बैंकिंग विवरण उपलब्ध है तो पुलिस तकनीकी जांच के माध्यम से इन लेन-देन की पुष्टि कर सकती है।

ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होने का दावा- रेलवे कर्मचारी का कहना है कि उसने पैसे मांगने के दौरान हुई मोबाइल बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित रखी है,यदि यह रिकॉर्डिंग वास्तव में मौजूद है तो इसकी फोरेंसिक जांच से यह स्पष्ट हो सकता है कि बातचीत किसकी है और उसमें क्या कहा गया है, ऐसे मामलों में ऑडियो रिकॉर्डिंग जांच का महत्वपूर्ण आधार बन सकती है,लेकिन अंतिम निष्कर्ष केवल तकनीकी परीक्षण के बाद ही निकल सकता है।

रिश्ता तोड़ा,फिर भी पीछा नहीं छोड़ा शिकायतकर्ता का दावा- आवेदन में कहा गया है कि लगभग दो लाख रुपये देने के बाद शिकायतकर्ता ने महिला से हर प्रकार का संबंध समाप्त कर दिया,उसका आरोप है कि इसके बावजूद वर्ष 2026 में महिला उसके गृहग्राम सोनपुर पहुंची और मोहल्ले में जाकर कथित रूप से उसे दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध में फंसाने की धमकी देने लगी,यही नहीं,शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसके पिता के नाम दर्ज जमीन अपने नाम कराने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है, उसका कहना है कि यदि जमीन नहीं दी गई तो दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जेल भिजवाने की धमकी दी जाती है।

पैसे देने से इंकार किया तो थाने पहुंच गई शिकायत

रेलवे कर्मचारी का आरोप है कि पैसे देने से मना करने के कुछ दिनों बाद महिला ने उसके खिलाफ रामानुजनगर थाने में शिकायत दर्ज करा दी, इसके बाद 12 जून 2023 को उसे तत्काल थाने बुलाया गया, यहीं से शिकायत का सबसे गंभीर हिस्सा सामने आता है, आवेदन में आरोप लगाया गया है कि थाने में उसे जेल भेजने,नौकरी खत्म होने और गंभीर कार्रवाई का डर दिखाया गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि उस पर महिला को डेढ़ लाख रुपये देने का दबाव बनाया गया, यदि यह आरोप सही साबित होते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह उठेगा कि पुलिस ने शिकायत की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं की और यदि मामला आपराधिक था तो विधिक कार्रवाई के बजाय कथित आर्थिक समझौते की स्थिति कैसे बनी?

15 जून 2023 को दिए डेढ़ लाख रुपये,वीडियो बनाने का दावा

शिकायतकर्ता ने आवेदन में लिखा है कि पुलिस के दबाव और नौकरी चले जाने के भय से उसने 15 जून 2023 को संबंधित महिला के घर जाकर 1 लाख 50 हजार रुपये दे दिए, इतना ही नहीं, उसने दावा किया कि पूरे घटनाक्रम का वीडियो उसने चुपके से अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। उसके अनुसार वीडियो में संबंधित पुलिस अधिकारी तथा महिला की बातचीत भी रिकॉर्ड हुई है, यदि जांच एजेंसियों को यह वीडियो उपलब्ध कराया जाता है और वह तकनीकी जांच में सही पाया जाता है, तो यह पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकता है। फिलहाल इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

बसदेई चौकी से लेकर एसपी तक लगाई गुहार

रेलवे कर्मचारी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि उसने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत पहले बसदेई पुलिस चौकी में दी,उसका आरोप है कि वहां कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, इसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक सूरजपुर को आवेदन सौंपा,जब वहां से भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो अंततः उसने सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को शिकायत भेजी और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की।

अंजुमन कमेटी ने भी कराया समझौते का प्रयास

शिकायतकर्ता के अनुसार विवाद को समाप्त करने के लिए स्थानीय अंजुमन कमेटी ने कई बार मध्यस्थता की, 19 जुलाई 2026 को सोनपुर में सामाजिक बैठक भी आयोजित की गई,रेलवे कर्मचारी का आरोप है कि बैठक में भी उसे सार्वजनिक रूप से धमकी दी गई, अपशब्द कहे गए तथा मारपीट कराने और थाने में फंसाने की चेतावनी दी गई,यदि इस बैठक में अन्य लोग उपस्थित थे तो उनके बयान भी जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

पुलिसकर्मियों पर भी गंभीर आरोप

इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील पक्ष शिकायत में लगाए गए पुलिसकर्मियों से जुड़े आरोप हैं,रेलवे कर्मचारी का आरोप है कि उसे पुलिस के नाम पर डराया गया, जेल और नौकरी जाने का भय दिखाया गया,पैसे दिलाने के लिए दबाव बनाया गया,आज भी नए-नए नंबरों से फोन कर धमकाया जाता है, कुछ पुलिस कर्मचारियों द्वारा भी पैसे की मांग की जाती है,यदि इन आरोपों में सत्यता पाई जाती है तो मामला केवल कथित ब्लैकमेलिंग तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि पुलिस की जवाबदेही का भी गंभीर विषय बन जाएगा।

जिस अधिकारी का नाम शिकायत में, क्या उसी सिस्टम से होगी जांच?

शिकायत में एक पुलिस अधिकारी का नाम भी सामने आया है,ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि आरोप पुलिस विभाग के भीतर के व्यक्ति पर हैं तो जांच कितनी निष्पक्ष होगी? क्या मामले की जांच किसी स्वतंत्र अधिकारी से कराई जाएगी? क्या शिकायत में बताए गए ऑडियो,वीडियो और बैंक ट्रांजेक्शन का फोरेंसिक परीक्षण कराया जाएगा? क्या संबंधित पुलिसकर्मियों को जांच पूरी होने तक मामले से अलग रखा जाएगा? इन सवालों के जवाब ही इस जांच की विश्वसनीयता तय करेंगे।

आईजी के सामने बड़ी जिम्मेदारी

अब पूरा मामला सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष पहुंच चुका है,यदि शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य,बैंक लेन-देन और अन्य दस्तावेज प्रथम दृष्टया सही पाए जाते हैं तो निष्पक्ष जांच आवश्यक होगी,दूसरी ओर, यदि जांच में आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं तो कानून के अनुसार झूठी शिकायत या मिथ्या आरोपों के संबंध में भी वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

अब सभी की निगाहें जांच पर...

यह मामला फिलहाल एकतरफा शिकायत पर आधारित है,संबंधित महिला,शिकायत में नामित पुलिस अधिकारी तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों का पक्ष अभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है, निष्पक्ष पत्रकारिता की दृष्टि से उनका पक्ष भी जांच और रिपोर्टिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा,फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस अपने ही विभाग पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच कर पाएगी,या फिर यह शिकायत भी अन्य शिकायतों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगी? सरगुजा रेंज के आईजी के समक्ष अब केवल एक शिकायत नहीं,बल्कि पुलिस व्यवस्था की निष्पक्षता और जनता के भरोसे की परीक्षा भी है,यदि शिकायतकर्ता द्वारा बताए गए ऑडियो, वीडियो और बैंकिंग साक्ष्य जांच में सही पाए जाते हैं,तो यह मामला प्रदेश में पुलिस की कार्यप्रणाली पर व्यापक बहस का कारण बन सकता है। वहीं यदि आरोप निराधार सिद्ध होते हैं,तो जांच उसी स्पष्टता से यह भी सामने लाए कि वास्तविकता क्या थी,फिलहाल पूरे मामले की सच्चाई निष्पक्ष और तथ्यपरक जांच से ही सामने आ सकेगी।

नाबालिग से दुष्कर्म : दो दोषियों को आजीवन कारावास,पॉक्सो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

बच्चों के खिलाफ अपराध पर सख्त संदेश,पॉक्सो न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद

-संवाददाता-

सूरजपुर,23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सूरजपुर जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र से जुड़े नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों दोषियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय) आनंद प्रकाश वारियाल ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ऐसे मामलों में कानून के तहत कठोरतम दंड दिया जाएगा।

मार्च-अप्रैल 2025 की घटना, मां की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला- अदालत में प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार यह मामला मार्च-अप्रैल 2025 का है, नाबालिग पीड़िता की मां ने थाना विश्रामपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 70(2) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 4 एवं 6 के तहत अपराध दर्ज किया, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया और वैज्ञानिक एवं कानूनी प्रक्रिया के तहत विवेचना प्रारंभ की।

साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने माना दोषी- विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया, आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए, गवाहों के बयान दर्ज किए तथा सभी औपचारिकताएं पूरी कर समय पर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया, सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आरोप सिद्ध हैं। इसके बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

पर्यटन स्थल से जुड़ा मामला, सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठे सवाल- यह मामला केनापारा फिश पॉइंट से जुड़ा है, जो सूरजपुर जिले का एक प्रमुख पर्यटन और भ्रमण स्थल माना जाता है, यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटक भी पहुंचते हैं,इस घटना ने सार्वजनिक स्थलों, पर्यटन क्षेत्रों और सुनसान स्थानों पर बच्चों एवं किशोरियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता पैदा की है, यह भी सवाल उठता है कि ऐसे स्थानों पर निगरानी,सुरक्षा और जागरूकता को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

न्यायालय का समाज के नाम महत्वपूर्ण संदेश- फैसला सुनाते समय न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध केवल किसी एक परिवार के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ अपराध हैं, ऐसे मामलों में कानून किसी प्रकार की नरमी की अनुमति नहीं देता, न्यायालय ने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों की गतिविधियों पर संवेदनशील निगरानी रखें, उनसे नियमित संवाद बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध परिस्थिति या घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दें,ताकि समय रहते बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

तेज विवेचना और समयबद्ध सुनवाई बनी न्याय की आधारशिला- इस मामले में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई,समय पर आरोपियों की गिरफ्तारी, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन और समयबद्ध चार्जशीट प्रस्तुत किए जाने के कारण न्यायालय में सुनवाई प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकी। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों ने भी दोष सिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कड़ा फैसला बना नजीर- फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो न्यायालय का यह फैसला उन लोगों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है जो बच्चों के खिलाफ यौन अपराध करने का दुस्साहस करते हैं, यह निर्णय बताता है कि ऐसे मामलों में न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर कठोर दंड देने से पीछे नहीं हटेगा।

वर्दी में नशा,कार्रवाई सिर्फ निलंबन? 388 एमजी अल्कोहल की पुष्टि के बाद भी अपराध दर्ज नहीं,जनता पूछ रही-क्या कानून सबके लिए समान है?

वर्दी में नशा, कार्रवाई सिर्फ निलंबन? डायल-112 हादसे के बाद उठे कई बड़े सवाल

388 एमजी अल्कोहल की पुष्टि, सरकारी वाहन भी हुआ दुर्घटनाग्रस्त, आम नागरिक पर केस,वर्दीधारी पर सिर्फ विभागीय कार्रवाई क्यों?

-रवि सिंह-

मनेंद्रगढ़ 23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

एमसीबी जिले में डायल-112 में तैनात एक आरक्षक के ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में पाए जाने का मामला अब केवल विभागीय अनुशासन का विषय नहीं रह गया है,बल्कि कानून के समान अनुपालन और पुलिस की जवाबदेही पर भी गंभीर बहस छेड़ रहा है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार 19 जुलाई 2026 को थाना जनकपुर में डायल-112 वाहन में ड्यूटी के दौरान आरक्षक अविनाश गुप्ता द्वारा शराब सेवन किए जाने की पुष्टि चिकित्सीय परीक्षण और ब्रेथ एनालाइजर जांच में हुई, आदेश में यह भी उल्लेख है कि ब्रेथ एनालाइजर में 388 एमजी अल्कोहल पाया गया तथा इसी दौरान डायल-112 वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से आरक्षक को निलंबित कर रक्षित केंद्र संबद्ध करते हुए विभागीय जांच के आदेश जारी किए, लेकिन इस कार्रवाई के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या केवल निलंबन ही पर्याप्त कार्रवाई है?

बता दे की यह निर्विवाद है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबन की कार्रवाई विभागीय अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक कदम है,लेकिन जनता की अपेक्षा इससे आगे की भी है,यदि किसी मामले में विधिक प्रावधान लागू होते हैं,तो उनकी निष्पक्ष और समान रूप से पालना होना ही कानून के राज की सबसे बड़ी कसौटी है,अब निगाहें इस बात पर हैं कि विभागीय जांच के साथ-साथ क्या इस मामले के वैधानिक पहलुओं पर भी कोई स्पष्ट निर्णय सामने आता है,जनता के मन में उठ रहे सवालों का पारदर्शी उत्तर ही पुलिस व्यवस्था में विश्वास को और मजबूत कर सकता है।

क्या मीडिया में मामला आने के बाद हुई कार्रवाई?-घटना 19 जुलाई की बताई जा रही है, जबकि निलंबन आदेश 20 जुलाई को जारी हुआ, शहर में यह चर्चा भी है कि यदि मामला शुरू से ही स्पष्ट था,तो संबंधित वैधानिक कार्रवाई तत्काल क्यों नहीं की गई? क्या पहले इसे केवल विभागीय स्तर तक सीमित रखने की कोशिश हुई और बाद में मामला चर्चा में आने पर निलंबन की कार्रवाई सामने आई? इन सवालों के आधिकारिक उत्तर अभी सामने नहीं आए हैं।

रात की पेट्रोलिंग पर भी उठ रहे सवाल-इस घटना के बाद शहर में एक और चर्चा तेज हो गई है, नागरिकों का कहना है कि रात के समय कुछ पेट्रोलिंग वाहनों में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा कथित रूप से शराब सेवन कर ड्यूटी करने की शिकायतें पहले भी सुनने को मिलती रही हैं, इन चर्चाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यदि ऐसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं तो पुलिस प्रशासन के लिए यह गंभीर संकेत हो सकता है।

जब शराब पीने की पुष्टि हो गई तो आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं?

आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि आरक्षक ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में था, मेडिकल परीक्षण कराया गया और ब्रेथ एनालाइजर में अल्कोहल की पुष्टि हुई,साथ ही सरकारी डायल-112 वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का भी उल्लेख है,ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि यदि कोई आम नागरिक शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है, चालान बनता है, कई मामलों में अपराध दर्ज होता है और वाहन तक जब्त कर लिया जाता है। फिर जब एक वर्दीधारी सरकारी वाहन चलाते समय नशे में पाया गया, तो उसके मामले में केवल विभागीय कार्रवाई तक ही बात क्यों सीमित रही?

क्या कानून सबके लिए समान है?

पुलिस हमेशा यह संदेश देती है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन इस मामले ने जनता के बीच यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह सिद्धांत पुलिस विभाग के अपने कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होता है? यदि कोई निजी चालक शराब के नशे में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होती है, ऐसे में डायल-112 जैसे आपातकालीन सेवा वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद केवल निलंबन से क्या पूरा मामला समाप्त माना जा सकता है?

क्या लेगा औचक ब्रेथ एनालाइजर अभियान?

जनता का मानना है कि यदि पुलिस अधीक्षक स्वयं रात्रिकालीन पेट्रोलिंग का औचक निरीक्षण करें, डायल-112 और अन्य पेट्रोलिंग वाहनों की अचानक जांच करें, ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों का ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण कराएं, तो स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकती है, यदि सब कुछ सामान्य मिलता है तो अफवाहों पर विराम लगेगा, और यदि कहीं अनुशासनहीनता मिले तो समय रहते उस पर कठोर कार्रवाई संभव होगी।

सरकारी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ,नुकसान का जिम्मेदार कौन?

मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू सरकारी संपत्ति से जुड़ा है,यदि आदेश के अनुसार शराब के नशे में डायल-112 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो यह भी जांच का विषय है कि वाहन को कितना नुकसान हुआ? दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई? क्या केवल विभागीय जांच पर्याप्त है? क्या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े अन्य कानूनी प्रावधान भी लागू होते हैं? इन बिंदुओं पर अभी तक सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

पुलिस अधीक्षक की कार्रवाई पर दो नजरिए...

इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल निलंबन को अनुशासन के प्रति सख्त संदेश माना जा रहा है,यह स्पष्ट संकेत है कि विभाग ड्यूटी के दौरान शराब सेवन को गंभीर अनुशासनहीनता मानता है,दूसरी ओर, जनता का एक वर्ग यह भी पूछ रहा है कि यदि शराब सेवन की पुष्टि मेडिकल और ब्रेथ एनालाइजर से हो चुकी थी, तो क्या विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ लागू होने वाले वैधानिक प्रावधानों पर भी विचार नहीं होना चाहिए था?

जनता के मन में अब भी बाकी हैं कई सवाल

यह मामला केवल एक आरक्षक के निलंबन तक सीमित नहीं है, इससे कई महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आए हैं क्या ड्यूटी के दौरान शराब पीना केवल विभागीय अपराध है या कानूनी भी? यदि सरकारी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो वैधानिक कार्रवाई क्यों नहीं दिखी? क्या आम नागरिक और पुलिसकर्मी के लिए कानून का व्यवहार समान है? क्या भविष्य में ऐसे मामलों में एक समान नीति अपनाई जाएगी?

पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा होगी सर्वोच्च प्राथमिकता, हर पर्यटक की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी सरकार : मंत्री राजेश अग्रवाल

पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और आवश्यक सुविधाएं बढ़ाने के दिए निर्देश

-संवाददाता-

रायपुर,23 जुलाई 2026(घटती-घटना)।

सरगुजा, जशपुर सहित प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर बरसात के मौसम में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर उठी चिंताओं पर राज्य सरकार ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश में आने वाले प्रत्येक पर्यटक की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि बारिश के मौसम में जशपुर, मैनपाट, चित्रकोट, तीरथगढ़, राजपुरी जलप्रपात, दराबा सहित प्रदेश के अनेक प्राकृतिक पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में इन स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने पर्यटन विभाग एवं संबंधित जिला प्रशासन को सभी संवेदनशील पर्यटन स्थलों का तत्काल निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जहां आवश्यकता होगी, वहां तड़ित चालक (लाइटनिंग अरेस्टर) लगाए जाएंगे। इसके अलावा खतरनाक क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड, बैरिकेडिंग, सुरक्षा रेलिंग, प्रशिक्षित लाइफगार्ड, प्राथमिक उपचार केंद्र तथा आपदा राहत दल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही मौसम विभाग की चेतावनियों और आपदा प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। पर्यटन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ सुरक्षित पर्यटन की अवधारणा को भी प्राथमिकता दे रही है। प्रदेश के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर चरणबद्ध तरीके से आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद पूरी सुरक्षा और विश्वास के साथ ले सकें। उन्होंने प्रदेशवासियों एवं पर्यटकों से अपील की कि बारिश के मौसम में प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

देहदान कर अमर हुए समाजसेवी गणेश दास मानिकपुरी,अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए मेडिकल कॉलेज रायपुर को सौंपी गई पार्थिव देह

कोरिया जनसंपर्क अधिकारी विजय मानिकपुरी के पिता गणेश दास मानिकपुरी नहीं रहे,देहदान कर मानवता को दे गए अमर संदेश

समाजसेवा की अंतिम मिसाल,गणेश दास मानिकपुरी की पार्थिव देह मेडिकल कॉलेज को दान,नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई

जीवनभर समाज की सेवा,मृत्यु के बाद भी मानवता के नाम देहदान...गणेश दास मानिकपुरी को भावभीनी विदाई

रामायण के प्रख्यात टीकाकार एवं समाजसेवी गणेश दास मानिकपुरी पंचतत्व में विलीन, देहदान से रचा सेवा का नया अध्याय

कोरिया/रायपुर 23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले के जनसंपर्क अधिकारी विजय मानिकपुरी के पिता,प्रख्यात समाजसेवी,रामायण के प्रख्यात टीकाकार एवं देहदान संकल्पी श्री गणेश दास मानिकपुरी का बुधवार सुबह रायपुर स्थित उनके निवास दोन्दे खुर्द में आकस्मिक निधन हो गया, उनके निधन से सामाजिक,सांस्कृतिक, साहित्यिक, पत्रकारिता एवं जनसंपर्क जगत में गहरा शोक व्याप्त हो गया, समाज ने एक ऐसे व्यक्तित्व को खो दिया,जिसने अपना संपूर्ण जीवन सेवा, संस्कार, आध्यात्मिक चेतना और मानवीय मूल्यों के लिए समर्पित कर दिया था, उनके निधन की सूचना मिलते ही रायपुर स्थित निवास पर अंतिम दर्शन के लिए जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों,जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों,पत्रकारों,साहित्यकारों,सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं बड़ी संख्या में शुभचिंतकों का तांता लग गया। सभी ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई देते हुए उनके व्यक्तित्व और समाज के प्रति उनके अतुलनीय योगदान को स्मरण किया।

प्रदेशभर में शोक,33 जिलों के जनसंपर्क अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि- स्व. गणेश दास मानिकपुरी के निधन का समाचार मिलते ही प्रदेशभर में शोक की लहर दौड़ गई, छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में पदस्थ जनसंपर्क अधिकारियों सहित अनेक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों, साहित्यकारों तथा विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने शोक संदेश जारी कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, सभी ने एक स्वर में कहा कि श्री मानिकपुरी का निधन केवल उनके परिवार की नहीं,बल्कि पूरे समाज की अपूरणीय क्षति है, उनका जीवन समाजसेवा, नैतिकता और मानवीय संवेदनाओं का जीवंत उदाहरण था।

रामायण के प्रख्यात टीकाकार के रूप में बनाई विशिष्ट पहचान-गणेश दास मानिकपुरी केवल समाजसेवी नहीं थे,बल्कि वे रामायण के प्रख्यात टीकाकार के रूप में भी व्यापक सम्मान प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने वर्षों तक धार्मिक आयोजनों, सत्संगों एवं सामाजिक कार्यक्रमों में रामायण की सरल, सहज और जीवनोपयोगी व्याख्या प्रस्तुत कर लोगों को धर्म के साथ-साथ नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवीय मूल्यों का संदेश दिया,उनकी वाणी में केवल धार्मिक प्रवचन नहीं,बल्कि समाज को सही दिशा देने वाली जीवनदृष्टि होती थी,यही कारण था कि वे विभिन्न सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में विशेष रूप से आमंत्रित किए जाते थे।

स्पष्टवादिता, सादगी और सामाजिक सरोकारों से अर्जित किया सम्मान-श्री मानिकपुरी की सबसे बड़ी पहचान उनकी सादगी, स्पष्टवादिता और निर्भीक व्यक्तित्व था,उन्होंने कभी दिखावे की समाजसेवा नहीं की,बल्कि अपने कार्यों के माध्यम से समाज में विश्वास और सम्मान अर्जित किया,गरीब, जरूरतमंद और समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए वे हमेशा आगे रहते थे। सामाजिक सरोकारों से जुड़े हर विषय पर उनकी सक्रिय भागीदारी रहती थी, उनके विचारों ने अनेक लोगों को सकारात्मक सोच और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करने के लिए प्रेरित किया।

मृत्यु से पहले ही लिया था देहदान का संकल्प- समाजसेवा को उन्होंने केवल अपने जीवन तक सीमित नहीं रखा,उन्होंने अपने जीवनकाल में ही एक ऐसा निर्णय लिया,जो मृत्यु के बाद भी मानवता की सेवा का माध्यम बन गया, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज),रायपुर को अपनी पार्थिव देह दान करने का विधिवत संकल्प लिया था और इसके लिए आवश्यक सहमति-पत्र भी भर रखा था,उनके निधन के बाद परिजनों ने उनकी अंतिम इच्छा का पूर्ण सम्मान करते हुए उनकी पार्थिव देह मेडिकल कॉलेज रायपुर को दान कर दी,यह निर्णय उपस्थित सभी लोगों के लिए भावुक और प्रेरणादायी क्षण बन गया।

मृत्यु के बाद भी समाज की सेवा का संदेश- श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने कहा कि अधिकांश लोग समाजसेवा की बातें करते हैं,लेकिन श्री गणेश दास मानिकपुरी ने अपने जीवन के साथ-साथ मृत्यु के बाद भी समाज की सेवा का मार्ग चुना,देहदान चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा अनुसंधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है,मेडिकल विद्यार्थियों को मानव शरीर की संरचना का अध्ययन कराने में ऐसे दान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनके इस निर्णय ने समाज को यह संदेश दिया कि मृत्यु के बाद भी मानव जीवन दूसरों के लिए उपयोगी बन सकता है।

मानवता के प्रति समर्पण का अद्भुत उदाहरण-श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, पत्रकारों और समाजजनों ने कहा कि श्री मानिकपुरी ने अपने जीवन में सेवा,त्याग और मानवता की जो मिसाल स्थापित की, उसे उन्होंने अपने अंतिम निर्णय से और भी ऊंचाई प्रदान कर दी,वक्ताओं ने कहा कि देहदान केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मानव कल्याण और चिकित्सा विज्ञान के विकास में अमूल्य योगदान है। ऐसे निर्णय समाज में जागरूकता पैदा करते हैं और लोगों को देहदान जैसे पुनीत कार्य के लिए प्रेरित करते हैं।

विजय मानिकपुरी के प्रति संवेदनाएं व्यक्त-श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोगों ने कोरिया जिले के जनसंपर्क अधिकारी विजय मानिकपुरी एवं उनके समस्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की, सभी ने कहा कि एक पिता का साया खोना अपूरणीय क्षति है, लेकिन श्री गणेश दास मानिकपुरी अपने विचारों, संस्कारों और सेवा कार्यों के माध्यम से सदैव समाज के बीच जीवित रहेंगे।

समाज को दे गए अमर संदेश- स्व. गणेश दास मानिकपुरी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति का मूल्य उसके पद, प्रतिष्ठा या संपत्ति से नहीं, बल्कि समाज के लिए किए गए कार्यों से तय होता है, उन्होंने अपने जीवन में धर्म को आडंबर नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम बनाया, समाजसेवा को दायित्व माना और मृत्यु के बाद देहदान कर यह सिद्ध कर दिया कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य भी मानवता की सेवा ही हो सकता है, उनकी विदाई केवल एक व्यक्ति की विदाई नहीं, बल्कि समाजसेवा के एक ऐसे युग का अवसान है, जिसने अपने कर्मों से हजारों लोगों को प्रेरित किया। आज वे भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी सादगी, विचार, समाजसेवा, रामायण की व्याख्याएं और देहदान का महान निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे।

सहयोग फाउंडेशन का हुआ शुभारंभ, समाजसेवा के लिए समर्पित रहेगा संस्थान

-संवाददाता-

प्रतापपुर,23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

समाजसेवा एवं जनकल्याण के उद्देश्य से स्थापित सहयोग फाउंडेशन का शुभ उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक माननीय श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने अपने कर-कमलों द्वारा सहयोग फाउंडेशन का विधिवत उद्घाटन करते हुए संस्था के सेवा कार्यों की सराहना की तथा इसके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दीं। सहयोग फाउंडेशन एक चैरिटेबल (धर्मार्थ) संस्था है, जिसका उद्देश्य समाज के जरूरतमंद एवं वंचित लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, वस्त्र, आश्रय तथा अन्य जनकल्याणकारी कार्यों के माध्यम से सेवा करना है। संस्था का लक्ष्य मानवता, सहयोग सेवा की भावना के साथ समाज के हर वर्ग तक सहायता पहुँचाना है।

संस्था के संस्थापक सदस्य हैं—शिवम गुप्ता, सौरभ गुप्ता, विलियम मिंज, शुभम जायसवाल नीलकंठ यादव, एवं ऋषभ गुप्ता। कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम पंचायत सेमरा खुर्द के सरपंच रूपा मिंज एवं नागरिकों ने सहयोग फाउंडेशन के इस सेवा अभियान की सराहना करते हुए संस्था के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संस्था ने समाज के सभी लोगों से जनसेवा के इस अभियान में सहयोग देने का आग्रह किया।

हर तूफान एक सीख है और... शादी के 4 महीने बाद अलग हुए बादशाह और ईशा रिखी? क्रिप्टिक पोस्ट ने बढ़ाई टेंशन

बादशाह की दूसरी पत्नी ईशा रिखी के एक क्रिप्टिक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है। कपल के 4 महीने के बाद शादी टूटने की खबरों ने जोर पकड़ा। रैपर बादशाह और विवादों का नाता एक-दूसरे से काफी गहरा है। वह कभी अपने गानों को लेकर तो कभी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में बने ही रहते हैं। इस बार बादशाह अपनी पत्नी ईशा रिखी की वजह से फिर चर्चा में आए हैं।चार महीने पहले पंजाबी रैपर बादशाह संग शादी के बंधन में बंधी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जिसे देखने के दोनों की शादी टूटने की खबरों ने सोशल मीडिया पर जोर पकड़ा है।

बादशाह की पत्नी के पोस्ट ने बढ़ाई फैंस की चिंता

ईशा रिखी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम

अकाउंट पर कुछ घंटे पहले एक वीडियो पोस्ट किया। यह एक मोंटाज हैं, जिसमें उनके और बादशाह के कुछ खूबसूरत पलों को उन्होंने कैद किया है। इस पोस्ट के साथ जो उन्होंने कैप्शन में लिखा है, वह देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कपल के बीच सबकुछ ऑल इज वेल नहीं है। ईशा रिखी ने फोटो मोंटाज के साथ कैप्शन में लिखा, हर तूफान एक सीख है और हर प्रार्थना एक उम्मीद है।÷ इस कैप्शन के साथ बादशाह की पत्नी ने एक हार्टब्रेक और हाथ जोड़े इमोजी लगाया है। इस पोस्ट को देखकर नेटिजन्स ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि कपल एक-दूसरे से सेपरेट हो चुका है। यूजर्स ने कहा- भगवान न्याय करे

ईशा रिखी ने न तो पोस्ट में बादशाह को टैग किया और न ही अपने रिलेशनशिप इशू के बारे में कुछ कहा। हालांकि, उन्होंने जो पोस्ट शेयर किया है, उसने सोशल मीडिया यूजर्स के दिल में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए जैस्मिन भसीन ने लिखा, आप खुद को मजबूत रखो एक यूजर ने लिखा, इस सीख की बहुत जरुरत थी। दूसरे यूजर ने लिखा,आपने ऐसा पोस्ट क्यों डाला है, उम्मीद करते हैं कि आपके और बादशाह के रिश्ते में सबकुछ सही हो। अन्य यूजर ने लिखा, समझ नहीं आया कि आप दोनों साथ हो या फिर आपका रिश्ता खत्म हो गया है। आपको बता दें कि यह बादशाह की दूसरी शादी थी, इससे पहले जैस्मिन मसीह से की थी।

विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन का रिव्यू

साउथ सुपरस्टार और अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म जन नायगन आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। लंबे इंतजार,विवादों और सेंसर बोर्ड से जुड़ी परेशानियों के बाद फिल्म दर्शकों के सामने है। यह फिल्म इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि राजनीति में सक्रिय होने के बाद विजय की यह आखिरी फिल्म बताई जा रही है। ऐसे में फैंस के लिए यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि उनके पसंदीदा अभिनेता की सिनेमाई यात्रा का आखिरी पड़ाव भी है।

फिल्म को लेकर पिछले कई महीनों से जबरदस्त चर्चा थी। निर्माताओं और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के बीच विवाद के बाद फिल्म में कई बदलाव किए गए। कई संवादों को म्यूट किया गया और कुछ दृश्यों पर कट लगाए गए। इसके बाद फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज की अनुमति मिली।

क्या है जन नायगन की कहानी?

फिल्म की कहानी थलपति वेट्री कोंडन (विजय) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो जेल में बंद है। कहानी में एक पुलिस अधिकारी की मौत के बाद उसकी आखिरी इच्छा के रूप में विजय के किरदार को उसकी बेटी विजी (ममिता बैजू) की जिम्मेदारी मिलती है।

थलपति विजी को मजबूत बनाना चाहता है और उसे सेना में जाने के लिए प्रेरित करता है। इसी बीच देश का दुश्मन जॉन हिमलर (बॉबी देओल) एक बड़ी साजिश रचता है। अफ्रीका में तबाही मचाने के बाद अब उसका निशाना भारत होता है। वह प्रोजेक्ट एमएम नाम की योजना के जरिए देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। जब थलपति और जॉन आमने-सामने आते हैं तो दोनों के बीच पुराने रिश्ते और अतीत के कई राज सामने आते हैं। इसके बाद कहानी एक्शन, संघर्ष और देशभक्ति के रंग में आगे बढ़ती है।

बड़े मुद्दों के बीच भटकती कहानी फिल्म के निर्देशक एच विनोद ने कहानी और पटकथा दोनों संभाली है। फिल्म में विजय को एक बड़े नेता और सुपरहीरो जैसी छवि में दिखाने की कोशिश की गई है। उनकी एंट्री से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक तक हर चीज को भव्य बनाया गया है। फिल्म में कई ऐसे संवाद हैं जो सीधे विजय के राजनीतिक सफर से जुड़ते हुए नजर आते हैं। जनता के नेता, लोकतंत्र की रक्षा और लोगों के अधिकार जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी गई है। कई जगह ऐसा महसूस होता है कि फिल्म विजय के राजनीतिक करियर की छवि को मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

कभी रात को ढाई बजे सड़क पर बैठा एक्टर,रेखा के प्यार में था पागल

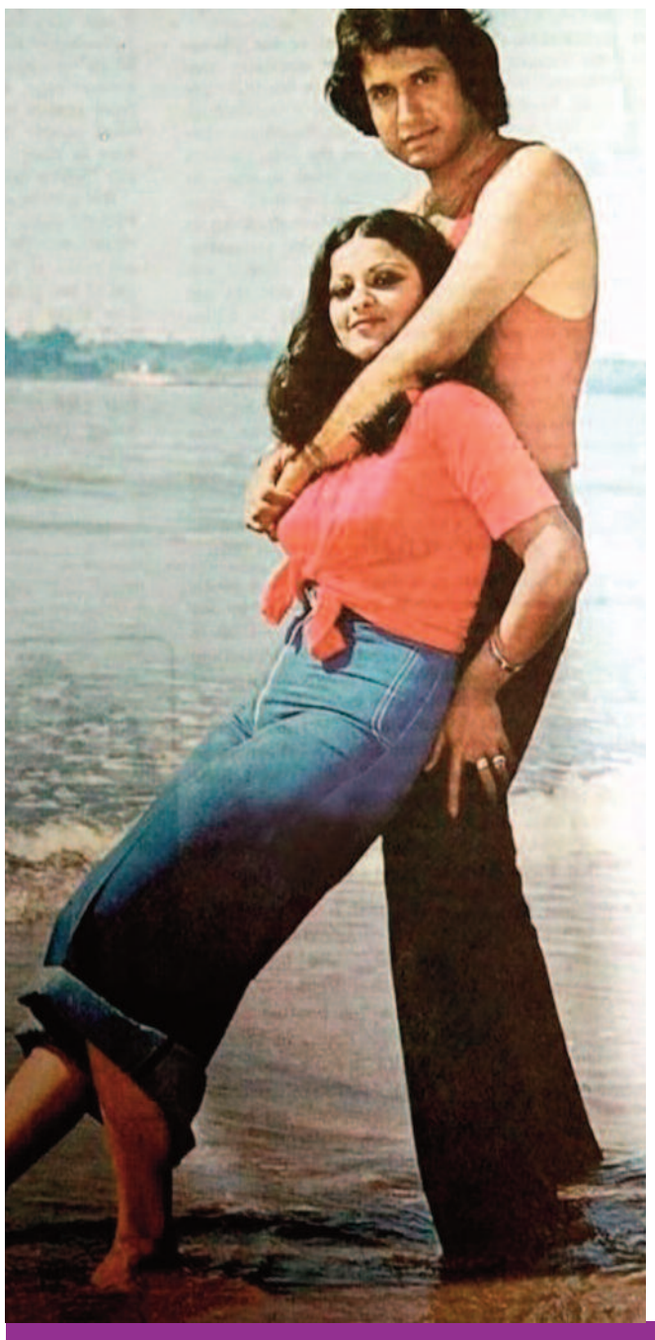

अब अक्षय की फिल्म से मिला नया जीवन

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ने अक्षय कुमार की फिल्म से कमबैक किया। कभी वह रेखा के प्यार में दीवाने थे।

सिनेमा जगत किस्सों-कहानियों से भरी हैं। ऑन-स्क्रीन छोड़िए...सितारे रियल लाइफ डेटिंग-ब्रेकअप को लेकर सुर्खियां बटोरते थे। हिंदी सिनेमा का एक अभिनेता थे जो आधी रात को शराब पीकर बीच सड़क पर ही बैठ गए थे और सलमान खान को लेकर अपने दिल की बात जाहिर कर रहे थे।

इतना ही नहीं, इस अभिनेता ने बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन रेखा के साथ अफेयर को लेकर भी खूब लाइमलाइट चुराई। यह अभिनेता कोई और नहीं, किरण कुमार हैं।

सिनेमा में बनाई अलग पहचान

लीड हीरो न सही, लेकिन किरण कुमार ने सपोर्टिंग रोल्स में दर्शकों का ध्यान जरूर खींचा। वह तेजाब, खुदा गवाह, अग्नि, हेना जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। वह अक्सर फिल्मी वर्ल्ड में सपोर्ट करने के लिए खान परिवार की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। एक बार तो वह आधी रात को सड़क पर ही बैठ गए थे।

सड़क पर बैठ गए थे एक्टर

कुनिका सदानंद के साथ बातचीत में किरण कुमारने रिवील किया था कि वह एक दिन पार्टी से आ रहे थे। उन्होंने खूब शराब पी रखी थी। रास्ते में उन्हें सलमान खान और सलीम खान का ब्रांड बीइंग ह्यूमन का आउटलेट देखा। उसके बाहर सलमान की होर्डिंग देखी। वह गाड़ी से निकले और सड़क पर ही बैठकर उनका शुक्रिया करने लगे थे। उस वक्त वह बहुत पीए हुए थे और समय रात के ढाई बज रहे थे।

रेखा संग था अफेयर

किरण कुमार अपनी लव लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहे हैं। कहा जाता है कि दोनों ने कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट किया था। अमिताभ बच्चन से पहले रेखा, किरण के साथ रिलेशनशिप में थीं। ब्रेकअप के बाद 1975 में रेखा ने किरण को मम्माज ब्वॉय बताया था।

किरण कुमार का कमबैक

हाल ही में 90ह्य और 2000 के दशक में काम कर चुके किरण कुमार फिर से वेलकम टू द जंगल में नजर आए। फिल्म की सक्सेस के बाद अभिनेता ने एक पोस्ट के जरिए कहा कि इस फिल्म ने कई एक्टर्स को नया जीवन दिया। इस फिल्म में उनके किरदार को सराहा गया।

छात्रों के समर्थन में उतरीं आलिया भट्ट

देश में चल रहे छात्र विरोध प्रदर्शन के बीच बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज उठाई है। आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया के जरिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों के प्रति अपना समर्थन जताया और कहा कि उनका दिल पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से टूट गया, लेकिन छात्रों के हौसले और संकल्प ने उन्हें उम्मीद भी दी है। आलिया ने अपनी पोस्ट में छात्रों के संघर्ष और उनकी मेहनत का जिक्र करते हुए कहा कि हर छात्र के पीछे एक सपना, परिवार की उम्मीदें और कई तरह के त्याग जुड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्र केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो उन्हें समर्थन दे रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर व्यवस्था की उम्मीद रखते हैं।

अभिनेत्री ने लिखा कि पिछले कुछ दिनों में सामने आई घटनाओं ने उन्हें भावनात्मक रूप से प्रभावित किया है। हालांकि, छात्रों के साहस और दृढ़ निश्चय को देखकर उन्हें उम्मीद भी मिली है। उन्होंने कहा कि छात्रों का संघर्ष देश के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। आलिया ने अपनी पोस्ट में छात्रों की हिम्मत की तारीफ करते हुए लिखा कि वह उनके साहस के सामने नतमस्तक हैं। उनके अनुसार, छात्रों का संकल्प पूरे समाज के लिए एक आईने की तरह है, जो यह दिखाता है कि युवा अपने अधिकारों और भविष्य को लेकर कितने सजग हैं। उन्होंने आगे कहा कि छात्रों की आवाज को सुना जाना चाहिए और उनकी चिंताओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

खेल समाचार

विश्व कप 2027 के लिए खिलाड़ियों पर नजर

इंग्लैंड, 23 जुलाई 2026। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने आने वाले वर्षों के लिए पुरुष और महिला टीमों के घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस शेड्यूल में सबसे बड़ा आकर्षण 2027 की एशेज सीरीज है, जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित जंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा इंग्लैंड ने आईसीसी वनडे विश्व कप 2027 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज भी तय की है।

ऑस्ट्रेलिया में खेली गई पिछली एशेज सीरीज में हार झेलने के बाद इंग्लैंड की टीम अब अपनी घरेलू परिस्थितियों में वापसी करने की कोशिश करेगी।

साउथेम्प्टन पहली बार करेगा एशेज टेस्ट की मेजबानी

लंदन,23 जुलाई 2026। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अगले साल 2027 में होने वाले मेंस और वुमेंस एशेज सीरीज के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। इस ऐतिहासिक शेड्यूल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि साउथेम्प्टन पहली बार पुरुषों के एशेज टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा। 2023 की तरह ही 2027 में भी मेंस और वुमेंस एशेज सीरीज का आयोजन एक साथ किया जाएगा,जिससे महिला क्रिकेट मुकाबलों को लेकर भी दर्शकों में भारी उत्साह देखने को मिलने की उम्मीद है।

पुरुषों का एशेज 2027 शेड्यूल,पहला टेस्ट ट्रेंट ब्रिज में...

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की मेंस एशेज सीरीज की शुरुआत 18 जून 2027 से ट्रेंट ब्रिज में होने वाले पहले टेस्ट से होगी। इसके बाद दूसरा टेस्ट 30 जून से 4 जुलाई तक लॉर्ड्स में और तीसरा टेस्ट 8 से 12 जुलाई तक एजबेस्टन में खेला जाएगा। चौथा टेस्ट 21 से 25 जुलाई तक पहली बार साउथेम्प्टन, युटिलिटा बाउल में आयोजित होगा, जबकि पांचवां और अंतिम टेस्ट 29 जुलाई से 2 अगस्त तक लंदन के द ओवल मैदान पर खेला जाएगा। तो ये था मेंस एशेज का पूरा शेड्यूल, आइए अब

आपको बताते हैं वुमेंस एशेज का शेड्यूल

महिला एशेज और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन

मल्टी फॉर्मेट महिला एशेज सीरीज की शुरुआत 24 जून से हेडिंग्ले में एकमात्र टेस्ट मैच के साथ होगी। साल 2001 के बाद यह पहला मौका होगा जब महिला टीम हेडिंग्ले में एशेज टेस्ट खेलेगी। इसके अलावा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 9 जून 2027 से लंदन के ऐतिहासिक द ओवल मैदान पर खेला जाएगा। ईसीबी ने यह भी पुष्टि की है कि 2029 और 2031 के फाइनल की मेजबानी भी इंग्लैंड ही करेगा।

इंग्लैंड का व्यस्त समर शेड्यूल

एशेज के अलावा इंग्लैंड की पुरुष टीम का यह समर सीजन काफी व्यस्त रहने वाला है। 15 मई से साउथेम्प्टन में पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज से घरेलू सीजन का आगाज होगा। इसके बाद 28 मई से लॉर्ड्स के मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ एक-ऑफ टेस्ट मैच खेला जाएगा। समर के उत्तरार्ध में इंग्लैंड न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगा। रिचर्ड गोल्ड ने बयान जारी करते हुए कहा कि पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया यहां आई थी, तो दोनों टीमों ने जिस तरह वापसी की,उसने क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचित कर दिया था और अगला समर फैंस के लिए बेहद खास होने वाला है।

न्यायालय नायब तहसीलदार भैयाथान ,जिला-सूरजपुर,छ0ग0

रा.प्र.क्र. /ब/121 वर्ष
ग्राम -रगदा पह0न0-14

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक विजेन्द्र कुमार पिता जागरसाय जाति रजवार निवासी ग्राम दगदा पह0न0-14 रा0नि0म0 भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर छ0ग0 द्वारा पेश किया गया है कि आवेदक के पुत्र जावेन्द्र कुमार राजवाड़े आ. विजेन्द्र कुमार का जन्म दिनांक 13/06/2012 को ग्राम रगदा मे हुई है अज्ञानतावश जन्म पंजियन नहीं करा पाया है आवेदक अपने पुत्र जावेन्द्र कुमार राजवाड़े का जन्म पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत रगदा को आदेशित करने आवेदन पेश किया है जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायायल में विचाराधीन है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 28/07/26 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते है नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार किया जावेगा ।

आज दिनाँक 23/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

सील **कार्यपालिक दण्डाधिकारी भैयाथान,जिला-सूरजपुर**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार-2 ,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा.प्र.क्र./अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक हिमांशु मिंज आ0 प्रबोध मिंज, जाति उरांव निवासी साई मंदिर रोड भगवानपुर, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर. जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा ग्राम भगवानपुरखुर्द स्थित भूमि खसरा नंबर 305/2, 309/1 रकबा क्रमशः 0.110. 0.220 हे0 के राजस्व अभिलेखों में पंजीबद्ध वसीयतनामा दिनांक 08/01/2026 के आधार पर वसीयतकर्ता संजय तिग्गा आ0 सुरेश तिग्गा का नाम का नाम विलोपित करते हुए आवेदक का नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 19/08/2026 से पूर्व न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 22/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

सील **अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-02**

न्यायालयअतिरिक्त तहसीलदार-2 ,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा.प्र.क्र./ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक दिलभरन उर्फ भाना आ0 स्व0 जयलाल, निवासी ग्राम कुदर, तहसील लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115, 116 के अंतर्गत आवेदन श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा0) अम्बिकापुर के समक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि आवेदक के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि कुल खसरा नंबर 10, कुल रकबा 0.990 हे0 भूमि ग्राम सकालो में स्थित है। उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में फौती नामांतरण के दौरान आवेदक का पुकारू नाम भाना दर्ज हो गया है। जबकि आवेदक का वास्तविक नाम दिलभरन आ0 जयलाल है। आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण नाम भाना को सुधार कर सही नाम दिलभरन आ0 जयलाल दर्ज कराये जाने का निवेदन किया गया है। जो जांच व प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 19/08/2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 221/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी ।

सील **अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-02**

नाम परिवर्तन सूचना

प्ररूप-(एक)

मै हरिशचन्द्र राजवाड़े माता/पिता/पालक का नाम) सुपुत्र/सुपुत्री नेतराम राजवाड़े , गाँव/शहर महुआटिकरा,पो0 भिट्ठीकला तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने नाबालिग सुपुत्र/सुपुत्री का नाम निशांत (NISHANT) (पुराना नाम) से बदल कर नेहरू राजवाड़े (NEHRU RAJWADE) (नया नाम) रख लिया है।

पालक
हरिशचन्द्र राजवाड़े
महुआटिकरा,पो0 भिट्ठीकला, अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

नाम परिवर्तन सूचना

प्ररूप-(एक)

मैं सिजय पिता घुरन उरांव, निवासी- ग्राम चौरा, थाना व तहसील राजपुर, जिला बलरामपुर (छ.ग.) ने अपने नाबालिग सुपुत्र / सुपुत्री का नाम बिदीया लकड़ा (BIDIYA LAKRA) से बदल कर बिंदिया लकडा (BINDIYA LAKRA) रख लिया है ।

पालक
सिजय
ग्राम चौरा,थाना-तह.-राजपुर
जिला-बलरामपुर,छत्तीसगढ़

विश्व विजेता टीम में बड़ा बदलाव

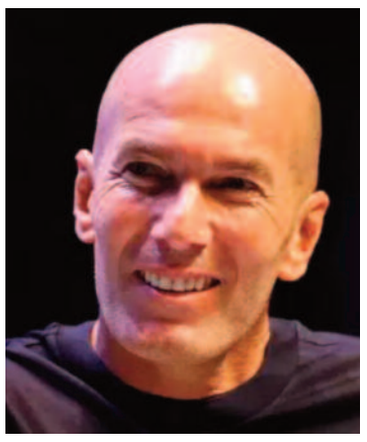

फ्रांस,23 जुलाई 2026।फ्रांस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बाद टीम के मौजूदा कोच दिदिए डैशचैंप्स के पद से हटने के बाद महान फुटबॉलर जिनेदिन जिदान को नया मुख्य कोच बनाए जाने की संभावना तेज हो गई है। फ्रांस फुटबॉल महासंघ जल्द ही नए कोच के नाम की आधिकारिक घोषणा कर सकता है। इस पद के लिए जिदान का नाम सबसे आगे चल रहा है। फ्रांस फुटबॉल महासंघ ने गुरुवार को जानकारी दी कि अध्यक्ष फिलिपे दियालो अगले मंगलवार को पेरिस स्थित महासंघ मुख्यालय से नए कोच के नाम का ऐलान करेंगे। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से किसी नाम की पुष्टि नहीं हुई है,लेकिन फुटबॉल जगत में चर्चा है कि जिदान को राष्ट्रीय टीम की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

रायपुर में खम्हारडीह थाने के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन

12 कांग्रेसियों पर एफआईआर से भड़के दीपक बैज,बोले...मंत्री-विधायकों पर भी दर्ज हो काउंटर केस

रायपुर,23 जुलाई 2026। रायपुर में भाजपा और कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हुआ। पुलिसकर्मियों के घायल होने पर 12 नामजद और कई अज्ञात कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं पर एफआईआर दर्ज की गई। अब इसके विरोध में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत कई नेता खम्हारडीह थाने में बीजेपी नेताओं-कार्यकर्ताओं पर काउंटर एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे हैं। थाने के बाहर बैठकर कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि बैज समेत कई नेता अंदर पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि, जितने मंत्री,विधायक और कार्यकर्ता आए, उन पर भी काउंटर एफआईआर दर्ज हो। दीपक बैज ने कहा कि,वो पत्थर मारेंगे,तो हम पुलिस के भरोसे बैठे रहेंगे क्या? फिलहाल,कांग्रेस नेताओं और पुलिस अधिकारियों से बातचीत का दौर जारी है। इससे पहले,प्रेस कॉन्फ्रेंस कर

प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं,हमने चूड़ियां नहीं पहनी हैं। बीजेपी की यह कार्रवाई पूरी तरह से बदले की भावना से प्रेरित है। कांग्रेस इस कानूनी और राजनीतिक कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देगी। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर सुनियोजित हमला किया गया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि, भाजपा सरकार कुछ ही महीनों की मेहमान है। रायपुर में बुधवार को राजीव भवन (कांग्रेस प्रदेश कार्यालय) के बाहर हुए भीषण उपद्रव और पथराव के मामले में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने खम्हारडीह थाने में लिखित शिकायत दी है। कांग्रेस ने बीजेपी के कई मंत्रियों, विधायकों और संगठन के दिग्गजों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

भाजपा-कांग्रेस झड़प मामले में 12 कांग्रेसियों पर एफआईआर दर्ज

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 22 जुलाई को भाजपा के कांग्रेस मुख्यालय घेराव प्रदर्शन के दौरान हुए भीषण बवाल में खम्हारडीह थाना पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है। खम्हारडीह थाना प्रभारी निरीक्षक भावेश कुमार गौतम की आधिकारिक शिकायत पर पुलिस ने कांग्रेस के 12 नामजद नेताओं समेत कई अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, बल प्रयोग करने और उपद्रव फैलाने की गंभीर धाराओं में अपराध कायम किया है। राजीव भवन के बाहर हुए इस टकराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर यह कड़ा वैधानिक कदम उठाया है। बता दे कि प्रधानमंत्री आवास के घेराव के विरोध में जब भाजपा कार्यकर्ता रायपुर स्थित राजीव भवन की ओर बढ़े, तो वहां स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। एफआईआर के मुताबिक, सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड्स की तरफ कांग्रेस कार्यालय की ओर से नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता तेजी से आगे बढ़े। पुलिसकर्मियों ने जब प्रदर्शनकारियों को रोकने और शांति बनाए रखने की अपील की, तब उग्र भीड़ ने धक्का-मुक्की शुरू कर दी। आरोप है कि उपद्रव के दौरान पुलिस बल पर कांच की बोतलें, पत्थर, लकड़ी और जूते फेंके गए, जिससे पीएसआई देवराज सिंह के सिर पर गंभीर चोट आई और महिला आरक्षक सीमा बंजारे का हाथ चुटैल हो गया।

ईडी को सुप्रीम कोर्ट से झटका! चैतन्य बघेल की जमानत रद्द करने से इनकार

रायपुर,23 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने उनकी जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) तथा एंटी करप्शन ब्यूरो, आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा की याचिकाएं खारिज कर दीं।

इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा दिया गया जमानत आदेश बरकरार रहेगा। चैतन्य बघेल को पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद जेल में रहते हुए ACB/EOW ने भी शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी दर्ज की थी। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद दोनों जांच एजेंसियों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया। जांच एजेंसी ईडी का आरोप है कि वर्ष 2019 से 2022 के बीच कथित शराब सिंडिकेट के संचालन में चैतन्य बघेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही और उन्होंने करीब 1,000 करोड़ रुपये के लेन-देन को संभाला। वहीं ACB/EOW का दावा है कि उन्हें सिंडिकेट से 200 से 250 करोड़ रुपये का हिस्सा मिला। हालांकि, अदालत ने अभी इन आरोपों पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है और मामले की सुनवाई जारी है। ईडी और EOW के अनुसार, छत्तीसगढ़ का कथित शराब घोटाला 3,200 करोड़ रुपये से अधिक का है। जांच एजेंसियों का दावा है कि तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में कथित शराब सिंडिकेट का गठन किया गया था, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों,आबकारी विभाग के अधिकारियों और कारोबारियों की भूमिका सामने आई है।

छत्तीसगढ़ कैडर की आईएफएस सातोविशा समाजदार एनएचआरसी में डायरेक्टर नियुक्त

रायपुर,23 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ कैडर की वर्ष 2010 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी सातोविशा समाजदार को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। यह महत्वपूर्ण नियुक्ति केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत नई दिल्ली स्थित एनएचआरसी मुख्यालय में की गई है। प्रशासनिक अनुभव और उत्कृष्ट कार्यशैली को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी है, जिससे राज्य कैडर की एक और वरिष्ठ अधिकारी को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी मिली है। इतिहास DoPT की ओर से जारी आदेश के अनुसार, आईएफएस सातोविशा समाजदार का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला देश का सबसे प्रमुख संवैधानिक निकाय है। डायरेक्टर के पद पर रहते हुए वे आयोग के प्रशासनिक, वित्तीय और प्रबंधन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण परिचालन कार्यों की सीधी देखरेख करेंगी।

दुर्ग में अब पूरी तरह डिजिटल होगी एफआईआर,छत्तीसगढ़ का पहला जिला बना

दुर्ग-भिलाई,23 जुलाई 2026। पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में दुर्ग जिले ने एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। दुर्ग, छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा जिला बन गया है जहाँ एफआईआर दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। अब यहाँ दर्ज होने वाली एफआईआर में जांच अधिकारी (विवेचक) के साथ-साथ शिकायतकर्ता के भी ई-साइन लिए जा रहे हैं।

यात्रा की गाइड और यात्रा की जानकारी : पुलिस विभाग के अनुसार, जिले के सभी विवेचक अब शत-प्रतिशत ई-साइन के ज़रिए ही प्राथमिक दर्ज कर रहे हैं। हाल ही में भिलाई नगर थाने में पुलिस मुख्यालय से मिली 'ई-पेन' की मदद से एक शिकायतकर्ता का पहला सफल ई-साइन कराया गया, जिसके साथ ही इस नई व्यवस्था

की औपचारिक शुरुआत हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस डिजिटल व्यवस्था से आम नागरिकों के लिए एफआईआर दर्ज कराना पहले से अधिक आसान, तेज और पारदर्शी हो जाएगा।

ई-साइन के उपयोग से सभी दस्तावेज़ पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे और सालों पुराने रिकॉर्ड को भी डिजिटल फॉर्मेट में आसानी से सहेजा जा सकेगा। कागजी कार्रवाई कम होने से समय की बचत तो होगी ही, साथ ही पुलिस प्रशासन 'पेपरलेस वर्क कल्चर' की ओर तेज़ी से बढ़ेगा। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने राज्य के थानों को विशेष 'ई-पेन' उपलब्ध कराए हैं। इसी डिवाइस की मदद से एफआईआर दर्ज करते वक्त शिकायतकर्ता और विवेचक, दोनों के डिजिटल हस्ताक्षर मौके पर ही दर्ज कर लिए जाते हैं।

हड़ताली अतिथि शिक्षकों को सरकार का अल्टीमेटम...27 जुलाई तक लौटें ड्यूटी पर नहीं तो सेवा होगी समाप्त

रायपुर,23 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षकों की जारी हड़ताल के बीच राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने का हवाला देते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि हड़ताल पर बैठे सभी अतिथि शिक्षक 27 जुलाई 2026 तक अपनी-अपनी शालाओं में लौटकर अध्यापन कार्य शुरू करें। निर्धारित समय-सीमा तक कार्य पर वापस नहीं आने वाले अतिथि शिक्षकों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएंगी। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से की गई थी। ऐसे में संबंधित शाला प्रबंधन समितियां सभी हड़ताली अतिथि शिक्षकों को 27 जुलाई तक विद्यालय में उपस्थित होकर पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दें।

नए विधानसभा भवन की फॉल्स सीलिंग गिरी,निर्माण की गुणवत्ता के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल...

रायपुर,23 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन में फॉल्स सीलिंग गिरने की घटना सामने आई है। इसने करोड़ों रुपए की लागत से बने भवन निर्माण की गुणवत्ता के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब घटना की तकनीकी जांच और निर्माण गुणवत्ता की स्वतंत्र समीक्षा की मांग उठने लगी है। घटना मुख्य सदन से लगे एक अधिकारी के कक्ष में हुई, जहां छत की फॉल्स सीलिंग के साथ स्टील के पाइप और फ्रेम भी नीचे आ गिरे। राहत की बात यह रही कि उस समय कमरे में कोई मौजूद नहीं था। फिलहाल, क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कराई जा रही है। इस घटना के बीच सूचना के अधिकार के तहत सामने आई एक जानकारी ने मामले को और गंभीर बना दिया है। लोक निर्माण विभाग ने आरटीआई

के जवाब में बताया है कि नए विधानसभा भवन का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। इसके बाद भवन के उपयोग और निर्माण प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी सार्वजनिक भवन के निर्माण के बाद निर्धारित मानकों के अनुरूप परीक्षण और औपचारिक प्रमाणन की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी होता है। ऐसे में फॉल्स सीलिंग गिरने की घटना और उपयोगिता प्रमाण पत्र को लेकर सामने आई जानकारी ने भवन की संरचनात्मक सुरक्षा पर बहस तेज कर दी है।

सेवा सेतु
जनता के द्वार, डिजिटल सरकार
आपकी ज़रूरत की सेवाएं
अब घर बैठे एक क्लिक में
प्रमुख सेवाएं
✓ जाति प्रमाण पत्र
✓ आय प्रमाण पत्र
✓ निवास प्रमाण पत्र
✓ विवाह प्रमाण पत्र
✓ राशन कार्ड सेवाएं
✓ पेंशन योजनाएं
✓ जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र
✓ व्यापार लाइसेंस
डिजिटल सुशासन की नई पहचान
सेवाएं हुईं त्वरित, पारदर्शी और आसान
श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
567 सेवाएँ
35 विभाग एक मंच पर
16,900+ सेवा केंद्र
44 लाख+ आवेदन
sewasetu.cgstate.gov.in
अधिक जानकारी हेतु स्कैन करें
जनहित में तकनीक, जनसेवा में नवाचार
sewasetu.cgstate.gov.in
92034 06400
संवाद 48530/57

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)